सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 326 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 09 सितंबर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को तीन नए जजों की सौगात, 11 से बढ़कर 14 हुई न्यायाधीशों की संख्या

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की अनुशंसा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की। तीनों नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और लंबित मामलों की सुनवाई में भी तेजी आने की उम्मीद है।

दो-तीन दिन में बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अभी बारिश की एक्टिविटी कम है, लेकिन अगले 2-3

दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी 10 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी बढ़ने के आसार हैं। वहीं 11 सितंबर के आसपास पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई। रायगढ़ के धरमजयगढ़ में 10 रूरूबारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा 34.5 डिग्री तापमान राजनांदगांव में रहा। वहीं सबसे कम 21.4 डिग्री तापमान पेंड्रा रोड और दुर्ग में दर्ज किया गया।

निर्मल कोसरे बने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एससी विभाग अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक

बदलाव के तहत अनुसूचित जाति (एससी) विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को नियुक्ति का आदेश जारी किया। पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ स्ट्र विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आदेश के मुताबिक, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। निर्मल कोसरे अब प्रदेश में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अवैध बैनर पोस्टर से पटा शहर पार्ट -3 ... भिलाई निगम के जोन-3 की सभी सड़कों पर दिख जाएंगे अवैध बैनर और पोस्टर

शहर की खूबसूरती बिगाड़ रहे अवैध बैनर-पोस्टर भिलाई निगम की मेहरबानी से फलता कारोबार

खानापूर्ति के लिए कार्रवाई, जुर्माना वसूल नहीं कर पा रहे जिम्मेदार

3 व 7 सितंबर को प्रकाशित खबर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। शहर की सुंदरता को बिगाड़ना हो तो नगर निगम भिलाई की कार्यशैली ही काफी है। हम लगातार अवैध बैनर पोस्टर से पटे खंबे और ट्यूबलर पोल की खबरें प्रकाशित कर रहे हैं इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। पिछले दिनों निगम प्रशासन ने अधिकृत रूप से विज्ञाप्ति जारी कर दो दिन में 1009 बैनर पोस्टर हटाने का दावा किया। अब सवाल यह है कि क्या पूरे शहर में नगर निगम प्रशासन को केवल 1009 बैनर पोस्टर ही मिले हैं। अब हकीकत हम बतातें हैं।

श्रीकंचनपथ समाचार पत्र द्वारा शहर के लगे अवैध बैनर पोस्टर को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। 3 सितंबर को जोन क्रमाक एक में लगे अवैध बैनर पोस्टर पर खबर प्रकाशित हुई। इसके बाद शनिवार यानी पांच सितंबर को निगम के प्रशासन द्वारा पांचों जोन में कार्रवाई का दावा किया गया और इससे संबंधित विज्ञप्ति भी जारी की गई। नगर निगम का दावा है कि इस दौरान पांचों जोन से कुल 1009 बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। इसके दो दिन बाद 7 सितंबर को श्रीकंचनपथ समाचार पत्र ने जोन क्रमांक 2 क्षेत्र में अवैध बैनर पोस्टर की खबर प्रकाशित की। यदि 5 सितंबर को निगम प्रशासन ने कार्रवाई की तो आखिर कहां? जोन क्रमांक 2 के कार्यालय के आसपास ही सैकड़ों बैनर पोस्टर खंबों पर लगे मिले। अब हम बात करते हैं जोन क्रमांक तीन मदर टेरेसा नगर की। इस जोन के बारे क्या कहना यहां की सड़कों पर एक एक खंबे पर एक से ज्यादा बैनर पोस्टर लगे हुए हैं।

अप्रैल में 15 दिनों के भीतर हटाए 800 से ज्यादा बैनर पोस्टर!

जोन क्रमांक 3 मदर टेरेसा नगर के क्षेत्र की बात करें तो यहां अप्रैल 2026 में 15 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाने का दावा किया गया। यह जानकारी जोन कार्यालय द्वारा एक आरटीआई में लगे सवाल के जवाब में दिया गया। अप्रैल में कार्रवाई की गई है तो इसके बाद दोबारा लगे अवैध बैनर पोस्टर पर नजर क्यों नहीं जाती। हमारी टीम ने जोन-3 के क्षेत्रों का भ्रमण किया तो देखा प्रमुख सड़कों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं।

क्या है निगम की मजबूरी, क्यों नहीं होती कार्रवाई

अवैध रूप से शहर की सड़कों पर लगे खंबों व ट्यूबलर पोल पर बैनर पोस्टर टांगने वालों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि निगम के अफ्सर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। आज के टेक्निकल जमाने में अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाने वालों तक पहुंचना बेहद आसान है इसके बाद भी निगम के जिम्मेदार अफ्सर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। केवल खंबों से बैनर पोस्टर हटा देने को ही निगम प्रशासन कार्रवाई समझ रहा है यह सही नहीं है। अवैध बैनर पोस्टर लगाने वालों से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाए तो व्यवस्था में सुधार संभव है।

करोड़ों के राजस्व का नुकसान फिर भी अफसर मौन

अवैध बैनर पोस्टर के कारण नगर निगम भिलाई को सालाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जो वेंडर्स विधिवत अनुमति लेकर होर्डिंग का किराया पटा रहे हैं एक तरह से उनके साथ यह अन्याय कर रहे हैं। बिना अनुमति शहर के प्रतिष्ठानों की प्रचार सामग्री बैनर पोस्टर के माध्यम से लगा रहे हैं। यह सभी ऐसे लोग हैं जो निगम के राजस्व को तो हानि पहुंचा रहे हैं साथ ही नियमानुसार काम कर रहे वेंडर्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना अनुमित खंबों पर प्रचार सामग्री टांगने वाले सालाना नगर निगम को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं इसके बाद अब तक एक बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं हो पाई है। कार्रवाई के नाम पर कुछ खंबों से बैनर पोस्टर हटाकर खानापूर्ति की जा रही है।

सीएम साय बोले- समस्या बताने बच्चियों को पैदल निकलना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं

- सरगुजा एकलव्य मामले पर मुख्यमंत्री हुए सख्तः लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के शिवपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं के अपनी समस्याओं को लेकर पैदल कलेक्टोरेट के लिए निकलने की घटना को गंभीरता से लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में लंबे समय से समस्याएं बने रहने और छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए इस तरह पैदल निकलने की स्थिति उत्पन्न होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर से कहा कि बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय से पैदल निकलना पड़े, यह स्थिति किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। यदि विद्यालय में लंबे समय से बिजली सहित अन्य समस्याएं बनी हुई थीं, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते उनका समाधान क्यों नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी अंचलों के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने छात्राओं द्वारा सामने लाई गई बिजली, शिक्षकों की कमी, नियमित पढ़ाई, मेस तथा साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे छात्राओं की समस्याएं विद्यालय एवं छात्रावास स्तर पर ही समय पर सुनी और दूर की जा सकें।

मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा और अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को किसी परेशानी के समाधान के लिए प्रशासन तक स्वयं पहुंचने की ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बच्चों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेना तथा समय पर उनका समाधान करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है। इन संसाधनों और योजनाओं का लाभ बच्चों तक सही ढंग से पहुंचे, यह सुनिश्चित करना मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

पहली से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग

- नक्सलमुक्त नहीं अब योगयुक्त कहलाएगा बस्तर
- 800 योग शिक्षकों को प्रशिक्षण, दूसरा बैच जल्द
- नक्सलगढ़ जगरगुण्डा से भी आगे आईं युवतियां

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सलमुक्त नहीं बल्कि योगयुक्त कहलाएगा। योग आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसके लिए पहली से दसवीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही योग शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उक्त बातें आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने श्रीकंचनपथ में चर्चा के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन चिकित्सा सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। योग आयोग योग को घर-घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए तृणमूल स्तर पर योग शिक्षक तैयार किये जा रहे हैं। पहले चरण में 800 योग शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों में योग को विषय के रूप में अनिवार्य किये जाने पर योग शिक्षकों को भी रोजगार मिलेगा। योग से साधारण स्वास्थ्य बेहतर रहेगा जिससे चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहे बोझ को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह तुम्हारा दूसरा कार्यकाल है। इसका लाभ तत्काल कार्ययोजना तैयार करने में मिला।

श्री अग्रवाल लंबे समय से पंतजलि पीठ से जुड़े रहे हैं और योग के क्षेत्र में गहरा अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पर यह भीड़ अभी जिम और प्रोटीन सप्लीमेंट की ओर बढ़ रही है। उनका विश्वास है कि योग का प्रचार प्रसार इसे सही दिशा देने में कारगर सिद्ध होगा। चर्चा के दौरान श्रीकंचनपथ के संपादक राजेश अग्रवाल, हर्ष मीडिया के संचालक हर्षित अग्रवाल, केपीन्यूज के प्रमुख सीमांत कश्यप सहित पूरा स्टाफ मौजूद था।

सेक्टर-2 के गटर में मिला नवजात : सीवरेज लाइन साफ करने पहुंचे कर्मियों ने देखी लाश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर-2 में सड़क नंबर 11 और 12 के बीच बुधवार को गटर की सफाई के दौरान करीब 3 दिन का नवजात शिशु मिला है। गटर की सफाई के दौरान कर्मचारियों को गटर के अंदर नवजात शिशु दिखाई दिया। नवजात की उम्र करीब दो से तीन दिन बताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर भट्ठी थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-2 में सड़क नंबर 11 और 12 के बीच गटर जाम था। पानी निकासी प्रभावित होने के बाद स्थानीय लोगों की ओर से बीएसपी प्रबंधन को इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद गटर की सफाई कराई जा रही थी। इसी दौरान सफाईकर्मियों की नजर नवजात पर पड़ी। नवजात के गटर में मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

पीएम मोदी की तीन घंटे की क्लास : राज्य मंत्रियों से पूछा- विकसित भारत के लिए खुद क्या किया?

नईदिल्ली। सोमवार को अपने 12 साल के कार्यकाल में दूसरी बार राज्य मंत्रियों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री बेहद सख्त शिक्षक के रूप में नजर आए। तीन घंटे की समीक्षा बैठक में मौजूद 20 राज्य मंत्रियों (3 स्वतंत्र प्रभार समेत) पर अलग-अलग सवालों की बौछार की।

राज्य मंत्रियों को आंकड़े रटने की आदत से बाज आने की नसीहत दी और एक-एक कर सभी मंत्रियों से विकसित भारत के संबंध में अपने-अपने एजेंडे को सामने रखने के लिए कहा। बैठक में ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण योजनाओं पर प्रजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री ने एक-एक

मंत्री से विकसित भारत निर्माण में व्यक्तिगत पहल की जानकारी देने केलिए कहा। इस दौरान जब मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से जुड़े आंकड़े गिनाने शुरू किए तो पीएम ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि सचिवों द्वारा बताए आंकड़े रटने की आदत छोड़ें। मंत्री के रूप में मिले बड़े अवसर के बाद आपने विकसित भारत बनाने, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने और राजग को लाभ दिलाने के लिए क्या किया है?

बैठक में पीएम ने हर मंत्री को टोका। एक मंत्री की मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाने से रोकते हुए पीएम ने पूछा- इसको छोड़िए, मंत्री बनने के बाद आप कितने आंगनवाड़ी केंद्र में गई हैं, कितने खिलौने बांटे हैं? एक अन्य मंत्री से पूछा कि उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों की उत्थान से जुड़ी पीएम स्वनिधि योजना के कितने लाभार्थियों से बात की है? व्यक्तिगत रूप से कितनों को इसका लाभ दिलाया है? इसी प्रकार पीएम ने बैठक में मौजूद सभी राज्य मंत्रियों से उनके व्यक्तिगत प्रयासों की जानकारी ली।

संपादकीय

बेलगाम अधिकारी

मनमानी कार्रवाई की जवाबदेही तय हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने के मामले जो टिप्पणियां की हैं, वो देश में राज्य सरकारों के लिये एक गंभीर चेतावनी समझी जानी चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए अफसरों के रवैये को तानाशाही वाला बताया है। कोर्ट ने बेहद सख्त भाषा का प्रयोग करते हुए राज्य को ऐसी जगह बताया जहां सरकार का निरंकुश नियंत्रण कानून-व्यवस्था के मामले में हो। स्पष्ट शब्दों में अदालत ने इस घटनाक्रम को मनमाने ढंग से आजादी छीनने वाला बताया। निश्चित रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार छात्रा की हिरासत को रद्द करने का कोर्ट का फैसला कई गंभीर प्रश्नों को भी जन्म देता है। जो यह भी दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से एक सामान्य मामले में किया जा रहा है। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि एहतियाती तौर पर हिरासत में लेना एक असाधारण उपाय है। लेकिन इस गिरफ्तारी को तभी सही ठहराया जा सकता है जब इसे सिद्ध करने के लिये पुख्ता सबूत हों। यानी कि कोई व्यक्ति वास्तव में देश की सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सामान्य आपराधिक कानून का आसान विकल्प या असहमति की आवाज को दबाने का जरिया नहीं बन सकता है। बताया जाता है कि इस प्रकरण में, खबरों के अनुसार अदालत को कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे यह साबित होता हो कि छात्रा का हिंसा भड़काने में कोई सीधा संबंध रहा हो। उल्लेखनीय है कि मामले में लिप्त अधिकारी कोई ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, मसलन व्हाट्स ऐप संदेश या वीडियो उपलब्ध नहीं करा सके, जो यह साबित करता कि छात्रा ने लोगों को दंगे या तोड़-फोड़ के लिये उकसाया था। जिसके बाद ही अदालत ने अभियुक्त की हिरासत रद्द करने के आदेश दिए।

> “ निश्चित रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार छात्रा की हिरासत को रद्द करने का कोर्ट का फैसला कई गंभीर प्रश्नों को भी जन्म देता है। जो यह भी दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से एक सामान्य मामले में किया जा रहा है। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि एहतियाती तौर पर हिरासत में लेना एक असाधारण उपाय है। लेकिन इस गिरफ्तारी को तभी सही ठहराया जा सकता है जब इसे सिद्ध करने के लिये पुख्ता सबूत हों। यानी कि कोई व्यक्ति वास्तव में देश की सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो।

देश का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास इस बात का गवाह है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना एक जायज अधिकार रहा है। एक स्वतंत्र देश में तो यह अधिकार और सबल हो जाता है। निस्संदेह, किसी संवैधानिक लोकतंत्र में विरोध व प्रदर्शन में शामिल होने और हिंसा भड़काने के बीच फर्क बहुत अहम है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियां हैं। दरअसल, अदालत ने गिरफ्तारी के समय और आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने के दौरान सामने आई विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को घटना के बाद रची गई कार्रवाई जैसा बताया है। इस घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश है कि घटनाक्रम के लिये जिम्मेदार अधिकारियों से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इतना ही नहीं अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में इस बाबत टिप्पणी दर्ज की जाने का निर्देश दिया गया है। अदालत की सोच रही है कि जब कोई भी अधिकारी सरकारी ताकत का गलत ढंग से इस्तेमाल करता है, तो जवाबदेही सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं रह सकती है। जिसका निहितार्थ यह भी है कि सरकारी कर्मचारी जबर्दस्ती प्रयोग की जाने वाली ताकत के मालिक नहीं हैं, वरन सही मायने में वे उसके संरक्षक होते हैं। वास्तव में उनकी निष्ठा सत्ता के बजाय संविधान और कानून के प्रति ईमानदारी से होनी ही चाहिए। कहने का अभिप्राय यह भी कि लोकतंत्र शोर-शराबे वाले विरोध को तो झेल सकता है, लेकिन ऐसी नौकरशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो असहमति को व्यवस्था के लिये खतरा समझती हो। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में अदालत द्वारा की गई सख्त टिप्पणियां देश की राज्यों सरकारों के लिये एक नजीर जैसी हैं। खासकर बेलगाम अधिकारियों के लिये सबक है कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिये लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन नहीं किया जा सकता। किसी भी सख्त कानून का इस्तेमाल करने से पहले अधिकारियों को उसकी तार्किकता को जायज ठहराना चाहिए। अधिकारियों के धैर्य, संयम व विवेक से ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

चेक बाउंस विवादों में तकनीक बने समाधान

डॉ. सुधिर कुमार

जब तक हम प्री-लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिजिटल ऑटोमेशन को न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक तारीखों के इस जंजाल से राहत नहीं मिल सकती।

देश की अदालतों में करोड़ों लंबित मामलों में से एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस के मामलों की है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक, चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इनमें से अधिकांश विवाद वित्तीय लेन-देन से जुड़े असंतोष या छोटी-मोटी चूकों के कारण होते हैं। इसके बावजूद, एक साधारण-सा चेक बाउंस होने पर कानूनी नोटिस भेजने से लेकर अदालत में समन जारी होने, गवाही, जिरह और फैसले तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में माना है कि इन मुकदमों का अंतहीन चलना व्यापारिक जगत और न्यायपालिका, दोनों के लिए घातक है।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण और लैंडमार्क फैसले हैं। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मामले 'इन री: एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, 1881 (2020)' में बड़ी बेंच ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि देश की अदालतों में चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं और इनका अंतहीन चलना न्याय व्यवस्था व व्यापारिक माहौल, दोनों के लिए घातक है। इसके साथ ही, 'दशरत रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र' (2014) के ऐतिहासिक मामले में भी न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि पारंपरिक मुकदमेबाजी में वादी और प्रतिवादी, दोनों का धन, समय और मानसिक सुकून नष्ट होता है। न्यायालयों ने कई बार मध्यस्थता और त्वरित न्याय प्रणालियों पर जोर दिया है, क्योंकि जिस मामले को बैंक स्तर पर या चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है, उसे वर्षों तक कचहरी के चक्कर कटवाए जाते हैं।

इस स्थिति में हमें लीक से हटकर सोचना होगा और एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल अपनाना होगा, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित हो। यहां एक अनूठा और आधुनिक तरीका काम आ सकता है—'स्मार्ट-ब्रीच ऑटो-रेज़ोल्यूशन पोर्टल'। कल्पना कीजिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति का चेक बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस होता है, पारंपरिक कागजी प्रक्रिया शुरू होने के बजाय एक स्वचालित डिजिटल ट्रिगर सक्रिय हो जाए।

इस नए मॉडल के तहत, बैंक स्तर पर ही एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर काम करे, जो तुरंत संबंधित व्यक्ति के खाते से एक निश्चित डिजिटल पेनल्टी और मूल राशि का आंशिक या पूर्ण ट्रांसफर सुनिश्चित करे; बशर्ते दोनों पक्षों के बीच पहले से डिजिटल एग्रीमेंट हो। यदि राशि को लेकर विवाद है, तो मामला सीधे कोर्ट जाने के बजाय ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म पर डायवर्ट हो जाए।

ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा वर्चुअल कोर्ट रूम या मध्यस्थता मंच है, जहां कोई वकील, कोई तारीख और कोई कागजी फाइल नहीं होती। दोनों पक्ष घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं। एक प्रशिक्षित एआई-असिस्टेड मीडिएटर या डिजिटल एल्गोरिद्म दोनों पक्षों के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालकर 7 से 15 दिनों के भीतर एक बाध्यकारी समझौता प्रस्ताव तैयार कर देता है। यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है, तो उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल स्कोर स्वत: डाउन हो जाता है और उसके अन्य बैंक खातों पर स्वचालित डिजिटल होल्ड लग जाता है। यह तरीका न केवल अदालतों का बोझ कम करेगा, बल्कि आम आदमी को मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाएगा।

डिजिटल न्याय प्रणाली की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ, इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी जैसी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से डिजिटल हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए, ताकि मुफ्त या कम शुल्क में तकनीकी सहायता मिल सके। जब तक डिजिटल साक्षरता और समावेशी मॉडल विकसित नहीं होंगे, तब तक न्याय का स्थानीयकरण अधूरा रहेगा।

कानूनी ढांचे में दूरगामी बदलाव करते हुए सबसे पहले चेक बाउंस जैसे मामलों में प्री-लिटिगेशन मेडिएशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बैंक खाते से संदेश आते ही 15 दिनों की ऑनलाइन बातचीत के जरिए आधे से अधिक मामले अदालत पहुंचने से पहले ही सुलझ सकें। इसके साथ ही, कंपाउंडिंग यानी समझौते के नियमों का स्वत: क्रियान्वयन लागू होना चाहिए, ताकि आरोपी द्वारा डिजिटल माध्यम से मूल राशि व हर्जाना जमा करते ही, बिना अदालती चक्कर और जज की अनुमति के, मामला स्वत: समाप्त होकर सिस्टम से केस क्लोजर रिपोर्ट जारी हो सके।

चेक बाउंस के मामलों में लोग जेल जाने के डर से भागते फिरते हैं या कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर वर्षों तक तारीखें लेते रहते हैं। हमें जेल भेजने की पुरानी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से बाहर निकलकर कड़े वित्तीय दंड और दीर्घकालिक सिबिल पाबंदियों को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। जानबूझकर चेक बाउंस करने वालों पर चेक राशि का 3 से 5 गुना भारी जुर्माना लगाया जाए, जो सीधे पीड़ित को मिले, और उनका सिबिल स्कोर इतना गिरा दिया जाए कि वे अगले 5 वर्षों तक नया लोन या क्रेडिट कार्ड न पा सकें। जब व्यक्ति के वित्तीय जीवन पर सीधा प्रहार होगा, तो वह अदालती चक्कर काटने के बजाय समय पर भुगतान करना खुद-ब-खुद सीख जाएगा।

जब तक हम प्री-लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिजिटल ऑटोमेशन को न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक तारीखों के इस जंजाल से राहत नहीं मिल सकती।

लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

दुनिया का नया नक्शा हमारी धारणाओं को भी बदलता है

प्रियदर्शन

4 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का नया नक्शा मंजूर किया। इस पर मतदान में 164 देशों ने मुहर लगाई, छह देश मतदान से अलग रहे, जबकि अमेरिका ने विरोध में मत दिया। भारत ने भी इस नक्शे के पक्ष में वोट दिया। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि इस नक्शे में भारतीय राष्ट्र-राज्य की सीमारेखाओं के साथ छेड़छाड़ है।

असम से लगती अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा को 'चीनी रेखा' की तरह दिखाया गया है और नगालैंड-असम के बीच की रेखा गुम है। वहीं तिब्बत को भारतीय रेखा में दिखाया गया है। चीन ने भी इस नक्शे को मंजूरी दी है। भारत का कहना है कि वह समान-विश्व की भावना के साथ है और इसी के अनुरूप नक्शे का समर्थन किया है। लेकिन यह विवाद बताता है कि दुनिया का नक्शा बनाना आसान नहीं है।

वैसे भी धरती गोल है और रेखाविहीन है। दरअसल अब तक दुनिया का जो नक्शा चल रहा था, उसे सोलहवीं सदी में नक्शानवीस गेरार्डस मेर्काटर ने समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इस नक्शे में अफ्रीका एक-तिहाई छोटा है।

यूरोप, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड बड़े दिखाए गए हैं, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के देश भी अपने असल

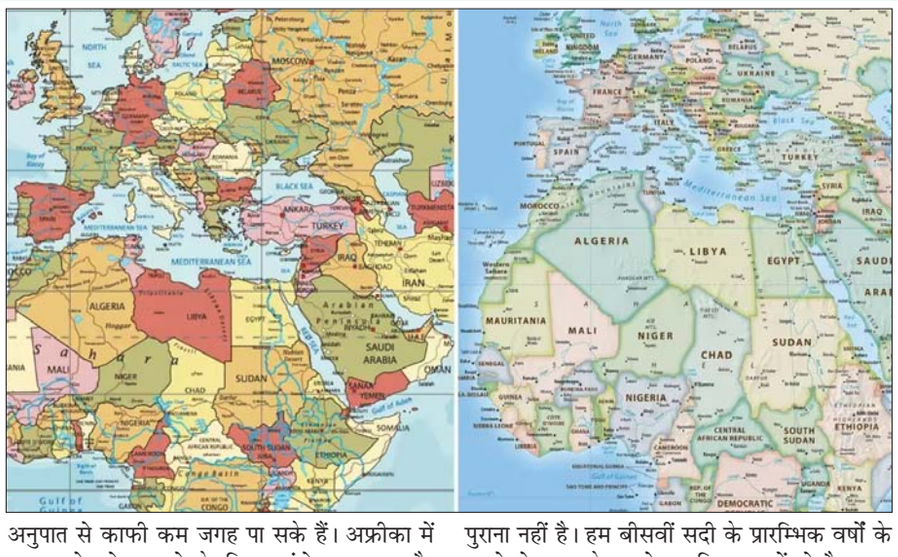

अनुपात से काफी कम जगह पा सके हैं। अफ्रीका में इस नक्शे को बदलने के लिए आंदोलन चला और अंतत: संयुक्त राष्ट्र की आमसभा ने मतदान से नया नक्शा मंजूर कर लिया।

यह नया नक्शा 2018 में नॉर्थ अमेरिकन कार्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत इक्वल अर्थ मैप' है। इसमें यूरोप पहले के मुकाबले सिकुड़ा हुआ है, ब्राजील फूला हुआ है और ग्रीनलैंड जैसे गुम हो चुका है। अफ्रीका को इसमें पूरी नुमाइंदगी मिली है।

लेकिन इस पर हुए विवाद ने याद दिलाया है कि दुनिया का नक्शा बदलता रहा है। कागजों पर बना जो एटलस हमारे दिमाग में छपा हुआ है, वह भी बहुत पुराना नहीं है। हम बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों के नक्शे से आज के नक्शे का मिलान करें तो हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के ताकतवर मुल्क कहां चले गए और कौन-से नए मुल्क नक्शे में उठ खड़े हुए?

बीसवीं सदी के प्रारंभिक 15 वर्षों के नक्शे में सोवियत संघ नहीं था, जो अचानक दुनिया की बड़ी ताकत बना और आखिरी दशक आते-आते लुप्त भी हो गया। बीसवीं सदी के ही पहले चार दशकों तक पाकिस्तान नहीं था और सात दशकों तक बांग्लादेश नहीं था। बीसवीं सदी के प्रारंभ में जो भारत था, उसकी सरहदें ईरान को छूती थीं। उसके पहले की शताब्दियों का कोई विश्व-यात्री पैदल चलता हुआ इस सदी में चला आए तो पहचान ही नहीं पाएगा कि जिस दुनिया से वह गुजरा था, वह कौन-सी थी।

यानी जिन सीमाओं को हम बिल्कुल ऐसे स्थायी मानते हैं, जैसे वे सभ्यता के उषाकाल से चली आ रही हों, वे दरअसल विकास के अलग-अलग दौर की राजनीतिक उथल-पुथल का परिणाम हैं। सभ्यताएं मुल्कों के राजनीतिक नक्शों से बड़ी और पुरानी होती हैं।

इंसानी सरोकार भी उस राजनीति से बड़े होते हैं, जो अकसर अपने स्वार्थों के लिए तमाम पहचानों का इस्तेमाल करती है और उन्हें आपस में लड़ाती भी है- फिर चाहे वे मुल्क हों या फिर मजहब हों। नया नक्शा बाध्यकारी नहीं है। यानी इसकी वजह से न मेर्काटर का मानचित्र मिटने वाला है, न पुराने ग्लोब तोड़े जाने हैं।

वे जहाजों की आवाजाही के लिहाज से अब भी कारगर हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर की सरकारों, स्कूलों और अंतरराष्ट्रीय निकायों से अपील करने वाला है कि वे जब भी स्थानों की तुलना करें तो नए नक्शे के हिसाब से करें।

यानी अब हमारे पास दुनिया को देखने के दो चश्मे होंगे, जो याद दिलाते रहेंगे कि न तो दुनिया इकहरी है और न ही हमारी नजर इकहरी होनी चाहिए। लेकिन हमें इस नक्शे में अपने हिस्से सुरक्षित-स्वीकृत चाहिए, यह निर्विवाद है।

दुनिया का नक्शा बदलता रहा है। कागजों पर बना जो एटलस हमारे दिमाग में छपा हुआ है, वह भी बहुत पुराना नहीं है। वास्तव में अगर हम बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के नक्शे से आज के नक्शे का मिलान करें तो हैरान रह जाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सवालों के जवाब देकर इस पीढ़ी की पीड़ा करें दूर

विश्वनाथ सचदेव

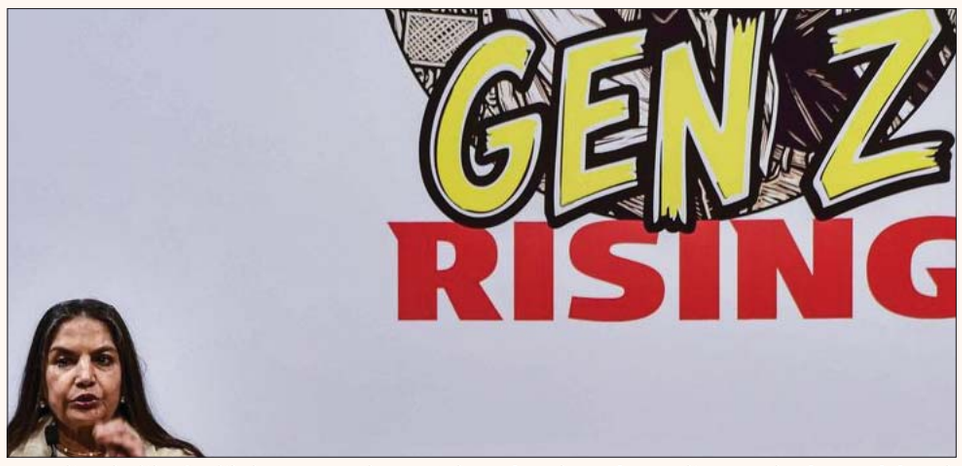

राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर इस पीढ़ी को समझना होगा। उसकी पीड़ा और उसकी नाराज़गी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह निराश है तो उसकी निराशा को समझने की कोशिश होनी चाहिए; वह सवाल उठा रही है तो उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए।

लगभग तेरह साल पुरानी बात है। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री-पद के उम्मीदवार थे। अपनी योग्यता-क्षमता को दिखाने के लिए उनके पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया गया काम था। उसी दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज में एक भाषण दिया था। उस भाषण में वह सब था, जो एक उम्मीदवार मतदाता को रिझाने के लिए कह सकता है। सपना दिखाया गया था, वादे किए गए थे। उस भाषण का एक जुमला बहुत चर्चित हुआ था तब—आधे भरे और आधे खाली गिलास वाला मुहावरा। आशावाद और निराशावाद का अंतर समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि वह आशावादी है, जो गिलास को आधा भरा हुआ बताता है और जो कहता है कि गिलास आधा खाली है, वह निराशावादी है। तब नरेंद्र मोदी ने इस मुहावरे में एक बात और जोड़ी थी, जिसने इस घिसी-पिटी बात को 'ताज़गी' दे दी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मुझे वह गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है—आधा पानी से, और आधा हवा से।'

तेरह साल बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के उसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को, और इसके बहाने देश को, संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अवसर कॉलेज के शताब्दी समारोह का था और जो विद्यार्थी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, वे तब शायद किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। जिन्होंने तेरह साल पहले वाला 'पूरे भरे गिलास' वाला भाषण सुना था, उन्हें वह याद भी था और मेरी तरह शायद वे यह उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे भरे गिलास वाली अपनी बात दोहराएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी अपनी कही उस बात को दोहराना ज़रूरी समझा। सामने बैठे विद्यार्थियों के लिए यह बात नई थी। उन्हें भी प्रधानमंत्री का आशावाद अच्छा लगा। तब भावी प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए थे, अब वर्तमान प्रधानमंत्री 'अपना रिपोर्ट कार्ड' लेकर उपस्थित थे। पिछले तेरह साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शायद स्वाभाविक था। खूब गिनाईं, और तालियां भी बजीं।

प्रधानमंत्री यह जानते थे कि कॉलेज में पढ़ने वाली जिस पीढ़ी को वे संबोधित कर रहे हैं, वह 'जेन ज़ी' नए मुहावरों को समझती है। देश के युवकों की एक अपनी भाषा है, अपना मुहावरा है उनका। प्रधानमंत्री ने कोशिश की उनसे उनकी भाषा में बात करने की। यह पीढ़ी सपने देखने के बजाय ठोस उपलब्धियों की जानकारी चाहती है। उपलब्धियां गिनाईं उन्होंने। पर यह 'जेन ज़ी' सवाल उठाने वाली है। उपलब्धियों को स्वीकारा जाना चाहिए, पर ऐसे मौके आत्मान्वेषण के भी होते हैं। यह अवसर एक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थान की शताब्दी का था। विद्यार्थी उस शिक्षा-स्थिति के बारे में भी सुनना चाहते थे, जो आज के भारत की चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले लगभग अस्सी साल में देश में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्थान खुले हैं। एक लंबी-चौड़ी सूची है हमारे पास नए-नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की। लेकिन यह सवाल भी उठता रहा है कि हमारे शिक्षा-संस्थानों को वैश्विक स्वीकार्यता क्यों नहीं मिल पाई। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर शिक्षा के उच्चतम पायदान पर दी जा रही शिक्षा आज सवालों के घेरे में क्यों है? गुणवत्ता और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर बनी चुनौतियों को हम कब देखेंगे—स्वीकारेंगे?

लगभग 17 साल पहले हमने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार को स्वीकारा था। सर्वशिक्षा अभियान जैसी पहल से स्थिति में कुछ सुधार आया है। पर प्राथमिक शिक्षा में जितना और जैसा सुधार अपेक्षित था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों के खुलने के समाचार मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति को लेकर पिछले कुछ दिनों में देश में ढेरों सवाल उठे हैं। एक-एक कमरे में चार-चार कक्षाएं एक साथ लग रही हैं। स्कूलों में टाट-पट्टी और शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधाओं का भी अभाव है। 'असर' जैसी संस्थाएं बार-बार इस स्थिति को उजागर कर रही हैं कि पांचवीं में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा।

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उसकी स्थिति भी कुल मिलाकर निराशाजनक ही है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई भी उस स्तर की नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी रोज़गार की अपेक्षाओं की शर्तों पर खरा उतर सके। उच्च शिक्षा के लिए हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में 'स्पेस सेंटर' बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं, पर धरती पर दुर्दशा की हकीकत की गंभीरता को कब समझा जाएगा?

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अपने चर्चित भाषण में प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास अवश्य किया है, पर पूरे भाषण पर चुनावी-साया दिखाई दे रहा है। यह अवसर एक प्रसिद्ध कॉलेज की शताब्दी का था और संयोग से उस दिन शिक्षक-दिवस भी था। यही नहीं, कुछ ही अरसा पहले देश ने 'जेन ज़ी' का असंतोष देखा था और इसी बीच ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की दुर्दशा का मसला भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में यह अपेक्षा तो होनी ही चाहिए थी कि प्रधानमंत्री देश में शिक्षा की स्थिति और समस्या पर कुछ कहेंगे। पर इस संदर्भ में कुछ विशेष नहीं कहा उन्होंने। देश की जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना भी ज़रूरी होता है, पर यह कतई ज़रूरी नहीं है कि हमारे राजनेता चुनावी माहौल से उबर ही न सकें। उबरना चाहिए उन्हें। भाषणों में जुमले और मुहावरे अच्छे लगते हैं, पर हमेशा नहीं।

शिक्षा-जगत से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने हवा से भरे हुए गिलास और 'दिमाग़ी नक्सल' वाली अपनी बातों को दोहराना ज़रूरी समझा, यह उनका विशेषाधिकार है। युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी अपनी कोशिश में भी कुछ ग़लत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है इस पीढ़ी से जुड़ना, उसकी आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना। पर 'नाराज़ फूफा' जैसे जुमले ऐसी कोशिशों को हल्का ही बनाते हैं। हमारे समय और समाज की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को समझने की ईमानदार कोशिश हो। राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर इस पीढ़ी को समझना होगा। उसकी पीड़ा और उसकी नाराज़गी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह निराश है तो उसकी निराशा को समझने की कोशिश होनी चाहिए; वह सवाल उठा रही है तो उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए।

बीबीसी ने श्रीराम कॉलेज के कार्यक्रम के बाद कुछ युवाओं से बातचीत की थी। उनमें एक युवक वह भी था, जिसे इसलिए कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वह काली कमीज़ पहने हुए था! उसने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि शायद आयोजकों को लगा था कि काली कमीज़ खतरे की घंटी है। मान लेना चाहिए कि उस युवक का कोई ग़लत इरादा नहीं था। उसका काली कमीज़ पहनकर आना एक संयोग हो सकता है। पर यह तय है कि देश की जेन-ज़ी अथवा जेन-अल्फा के पास कुछ सवाल हैं, जो उसे परेशान करते हैं। हमारे नेतृत्व को उनकी परेशानी को समझना होगा। तभी गिलास सही अर्थों में भरेगा।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें...

सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन दुर्ग में जलाएं जाएंगे सवा लाख दिए

दुर्ग। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार की संध्या विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। विडियो कांफ्रेंसिंग में कलेक्टर अभिजीत सिंह, अभियान के नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ बीके दुबे एवं अन्य विभागों के नोडल अधिकारी सहित विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े थे। प्रभारी मंत्री शर्मा ने अवगत कराया कि संभाग मुख्यालय दुर्ग में सेवा संकल्प अभियान की प्रथम दिवस संध्या पर सवा लाख आशीर्वाद का दीया जलाएं जाएंगे। इस हेतु विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दायित्व सौंपे गये हैं। उन्होंने कलेक्टर एवं अधिकारियों को बेहतर ढंग से सफल आयोजन का दायित्व सौंपते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थान चयन एवं समुचित तैयारी करने के निर्देश दिये। मंत्री शर्मा ने कहा कि इसी तरह जिले के नगरीय निकायों एवं विकासखंड मुख्यालयों में भी सामूहिक रूप से एक सुनिश्चित स्थान पर आशीर्वाद का दीया जलाने का पहल किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक सामंजस्य के साथ जिले में सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाया जाए।

श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी एवं श्रम कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य

दुर्ग। जिले में श्रम विभाग अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम कार्ड का ई-केवाईसी एवं अद्यतन संशोधन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विभागीय डेटाबेस को आधार के अनुरूप सत्यापित एवं संधारित करना है ताकि वास्तविक व पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की राशि व सुविधाएं सीधे पहुंच सकें। वर्तमान में श्रमिकों के डेटाबेस को आधार विवरण के अनुरूप अद्यतन करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में श्रम विभाग से संबंधित सी.एस.सी. संचालकों द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिक इन शिविरों अथवा निकटतम सीएससी. केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर अपने आधार कार्ड के अनुसार श्रम कार्ड का संशोधन ई-केवाईसी करा सकते हैं। विभागीय नियमानुसार, ई-केवाईसी के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक का विवरण आधार से लिंक किया जा रहा है। केवल ई. केवाईसी पूर्ण एवं अद्यतन श्रम कार्डधारी पात्र श्रमिक ही आगामी विभागीय योजनाओं के लाभ हेतु पात्र होंगे।

कनाडा से पहुंचे प्रोफेसर संदीप बेनर्जी आईआईटी भिलाई के इंटरसेक्शन व्याख्यान में पहुंचे

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के लिबरल आर्ट्स विभाग ने 7 सितंबर 2026 को इंटरसेक्शन व्याख्यान श्रृंखला के तत्वावधान में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के डॉ. संदीप बनर्जी द्वारा एक आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन किया। परिसर में आयोजित माउंटेन ग्लोम, माउंटेन ग्लोरी: एक्सकर्शन्स इनटू हिमालयन एस्थेटिक्स नामक व्याख्यान में, डॉ. बनर्जी ने उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत के बीच हिमालय पर निर्मित ग्रंथों और छवियों के एक सेट की जांच करके हिमालयी सौंदर्यशास्त्र की श्रेणी के बारे में बात की। व्याख्यान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे ये वस्तुएं - तस्वीरें, पेंटिंग, यात्रा लेखन और कविताएं - हिमालय को एक अनुभवात्मक स्थल के रूप में प्रस्तुत करती हैं। व्याख्यान में हिमालय का प्रतिनिधित्व करने में कलाकारों द्वारा अपनाई गई विभिन्न पाठ्य रणनीतियों और मानव-प्रकृति संबंधों को समझने के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा की गई।

हिमालय के प्रतिनिधित्व में समानता और अंतर पर जोर

डॉ. बनर्जी ने यूरोपीय और भारतीय लेखकों और कलाकारों के काम में हिमालय के प्रतिनिधित्व में समानता और अंतर पर जोर देकर बात समाप्त की। व्याख्यान ने एक जीवंत चर्चा उत्पन्न की जिसमें उपभोग के मुद्दों, मानवों के अपने पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण पर समकालीन चिंताओं और पाठ को पढ़ने के तरीकों को संबोधित किया गया। लिबरल आर्ट्स विभाग द्वारा आयोजित इंटरसेक्शन व्याख्यान श्रृंखला लिबरल आर्ट्स और उनकी शिक्षाशास्त्र, कार्यप्रणाली और प्रक्षेपवक्र की खुली चर्चा और परीक्षा के लिए एक बहु-विषयक मंच है इस मंच का उद्देश्य समकालीन सामाजिक और विद्वतापूर्ण जीवन में चिंतनशील, विचारशील भावना को फिर से केंद्रित करना है और इसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्रोफेसरों द्वारा आमंत्रित व्याख्यान शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर शुरू हुआ जनपरामर्श, दुर्ग में उच्च स्तरीय बैठक

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध जैसे मुद्दों पर सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने दिए सुझाव

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति ने जनपरामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार, 08 सितंबर को दुर्ग में यूसीसी प्रारूप समिति द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह की उपस्थिति में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

पारंपरिक मान्यताओं और कानूनी सुधारों पर चर्चा

बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संघों के पदाधिकारियों ने यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान पारंपरिक-सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी सुझावों का अध्ययन कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।

विविध संगठनों की रही सक्रिय सहभागिता

इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख रूप से साहू समाज, मनवा कुर्मी समाज, कंवर समाज, चंद्रनाहू कुर्मी समाज, गोंडवाना सेवा समिति, आंध्र समाज, हलवा समाज, ताम्रकार समाज, यादव समाज, कंडरा आदिवासी समाज एवं मुस्लिम समाज युवा प्रभाग के पदाधिकारी, सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गोंड महासभा, बीएसपी एसटी कर्मचारी संघ, भारतीय बौद्ध महासभा और राम मंदिर ट्रस्ट बेमेतरा के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी प्रकार नागरिक एवं व्यावसायिक मंच से वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच, प्रज्ञा वरिष्ठ नागरिक संघ, पेंशनर्स संघ, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य सुझाव देने वालों में शामिल थे।

डिजिटल माध्यम से भी आमंत्रित किए गए सुझाव

बैठक में एडवोकेट प्रांजल शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (च्ज) के माध्यम से समान नागरिक संहिता के स्वरूप और प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समिति ने आम जनता और संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाईट http//ucc.cgstate.gov.in एवं ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in भी साझा की है। बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सचिव एवं रायपुर संभाग आयुक्त श्याम धावड़े, दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, एडीएम वीरेंद्र सिंह और एसडीएम प्रफुल्ल गुप्ता सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

रिसाली शिविर में 68 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों का हुआ पंजीयन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग के सहयोग से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण मंत्रालय के निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निगमित सामाजिक दायित्व योजनान्तर्गत एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), रायपुर द्वारा दुर्ग जिले के दिव्यांगजनो एवं वरिष्ठजनों को नि:शुल्क सहायक उपकरण प्रदाय हेतु दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों हेतु मूल्यांकन, परीक्षण, चिन्हांकन शिविर का आयोजन न.पा.नि. रिसली, अमलेश्वर, पाटन, उतई व जनपद पंचायत पाटन के समस्त ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए स्थान नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग में शिविर आयोजित किया गया।

आयोजित शिविर में कुल 68 दिव्यांगजनो एवं वरिष्ठजनों का पंजीयन किया गया जिसमें से दिव्यांगजनों हेतु निम्न सामाग्री जैसे-मोटराईज्ड ट्रायसायकल, ट्रायसायकल, बैसाखी, व्हील चेयर, तथा वरिष्ठजनों हेतु श्रवण यंत्र, कमोड चेयर आदि उपकरणों को सहित कुल-187 सामाग्रियों के लिए चिन्हांकित किया गया। इस अवसर पर मोनिका वर्मा आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली तथा वार्ड पार्षदगण शैलेन्द्र कुमार साहू, सीमा साहू, माया यादव, सारिका साहू, सरिता देवांगन आदि उपस्थित रहे।

प्लॉट से मलबा हटाने के निर्देश कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम आयुक्त लीना कोसम ने आज सुबह स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, शोएब अहमद एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वार्ड क्रमांक 28 एवं 29 में मॉर्निंग विजिट कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सामने आई समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

आयुक्त ने निर्धारित कार्यों को दो दिवस के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है।निरीक्षण के दौरान पचरीपारा में खुले प्लॉटों में पड़े मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं वार्ड क्रमांक 28 एवं 29 की सभी नालियों की तल तक व्यापक सफाई कराने को कहा गया, ताकि

जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

वार्ड 28 में जनरल स्टोर के सामने सड़क पर कचरा पाए जाने पर संबंधित दुकान के विरुद्ध कार्रवाई एवं जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह कन्हैया ट्रेड हाउस के पास कचरा मिलने पर संबंधित दुकान पर जुर्माने की कार्रवाई करने तथा वार्ड की गलियों में अतिरिक्त पेड़ों की छंटाई कराने के निर्देश दिए गए।

शहर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली एमआईसी की मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरूचि सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास, निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नग हापर टिप्पर क्रय किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। महापौर परिषद ने पुन: निविदा करने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिए हैं।

जोन क्रमांक-03 अंतर्गत संतोषी पारा स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को संचालन, प्रबंधन एवं संधारण के लिए 10 माह की अवधि हेतु किराये पर दिए जाने संबंधी नियम एवं

शर्तों का अनुमोदन और निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई।

निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खुले मैदान, फुटपाथ, चौराहे एवं अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों पर पंडाल अथवा अस्थायी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार शुल्क लिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।

निगम द्वारा चंद्रा-मौर्या के सामने निर्माणाधीन हाईजिनिक फुड जोन के संचालन, अनुरक्षण एवं राजस्व साझेदारी के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य फूड जोन का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के साथ व्यवस्थित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में राजस्व अधिकारी की सेवावृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। स्वर्गीय वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नाम से चंद्रा मौर्या टॉकीज अंडरब्रिज के नामकरण किए जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सामान्य सभा को प्रस्ताव भेजा गया है।

नेहरू नगर क्षेत्र में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से नेहरू नगर अंडरब्रिज तक रेलवे लाइन के समानांतर सड़क निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य कराया जाएगा। यह कार्य लगभग 314.15 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण एवं विद्युतीकरण से क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

बैठक में लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, आदित्य सिंह, संदीप निरंकारी, एकांश बंछोर, लाल चंद वर्मा, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, चंद्रशेखर गंवई, नेहा साहू, अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, उपायुक्त सह जोन आयुक्त डी के कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे कुलदीप गुप्ता, अमरनाथ दुबे, कार्यापालन अभियंता अनिल सिंह, अरविन्द शर्मा, नितेश मेश्राम, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अशोक देवांगन, विनय शर्मा उपस्थित रहे।

क्विज से दिल्ली तक पहुंचेगा दुर्ग का युवा टैलेंट, 23248 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

- जिला पंचायत सीईओ ने स्कूल-कॉलेज, एनएसएस, एनसीसी और युवा संगठनों को भागीदारी के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। 'माई भारत-विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027' में दुर्ग जिले के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जिले में 23,248 युवाओं के पंजीयन एवं ऑनलाइन क्विज में सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। 'विकसित भारत क्विज' में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाता है। देशभर के

युवाओं को एक मंच पर लाने वाले इस आयोजन को वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के रूप में पुनर्गठित किया गया।

इसी क्रम में 30वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव-विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना तथा उनमें नेतृत्व, नवाचार और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है।

22 भाषाओं में क्विज, ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का मौका

'माई भारत' पोर्टल पर आयोजित विकसित भारत क्विज 22 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें भारत, भारतीय विरासत, देश की उपलब्धियों, विकास यात्रा तथा 'विकसित भारत 2047' से जुड़े विषयों पर युवाओं के सामान्य ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाएगा। क्विज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

पांच चरणों से होकर दिल्ली तक पहुंचेगा सफर

विकसित भारत चैलेंज ट्रेक तहत युवाओं का चयन पांच चरणों में होगा। पहला चरण ऑनलाइन क्विज का है, जो 17 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद 5 से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन निबंध लेखन, 10 से 16 नवंबर तक जिला चौंपियनशिप, 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक राज्य स्तरीय वीबीवाईएलडी और अंत में 10 से 12 जनवरी 2027 तक नेशनल डायलॉग प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय मंच पर रख सकेंगे अपना विजन

नेशनल डायलॉग इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित युवाओं को विकसित भारत से जुड़े अपने विचार एवं सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का मंच मिलेगा। निबंध एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से युवा विकसित भारत के निर्माण से जुड़े अपने विचार, विजन, नवाचार और समाधान प्रस्तुत करेंगे। जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।

स्कूल-कॉलेजों में स्टूडेंट्स के बीच चलेगा अभियान

बैठक में जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत, दुर्ग के प्रतिनिधि क्षितिज ने पंजीयन एवं क्विज की प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ बजरंग कुमार दुबे ने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, उच्च शिक्षा के जिला नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के प्राचार्य प्रधानाध्यापकों को युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आईटीआई, एएसएस, एनसीसी, स्काउट-गाइड व आईआईटी भिलाई सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

पहली बार लोकरंग पर्व में दिखी सरगुजा-जशपुर अंचल की आदिवासी लोक-संस्कृति की मनमोहक झलक

पंथी और नाचा-गम्मत ने भी मोहा दर्शकों का मन,सरहुल-करमा की थाप पर झूम उठा लोकरंग पर्व, लोक संस्कृति के रंगों से सजा समापन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत को मंच प्रदान करने वाले तीन दिवसीय 'लोकरंग पर्व' का तीसरा एवं अंतिम दिन सरगुजा-जशपुर अंचल की आदिवासी लोकसंस्कृति के नाम रहा। पहली बार लोकरंग पर्व के मंच पर जशपुर अंचल के सरहुल एवं करमा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों की मधुरता और कलाकारों के ऊर्जावान नृत्य ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया।

कार्यक्रम में श्री विजय कुमार भगत, जशपुर के दल द्वारा सरहुल एवं करमा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आदिवासी लोकजीवन, प्रकृति और सामुदायिक परंपराओं से जुड़े इन लोकनृत्यों ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया। कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति, पारंपरिक लय और आकर्षक वेशभूषा ने कार्यक्रम में विशेष रंग भर दिया। इसके साथ ही रायपुर के डॉ. रामनारायण नेताम ने आदिवासी लोकगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी।

नवलदास मानिकपुरी, दुर्ग ने लोकगीत-संगीत से समां बांधा। वहीं सुश्री आरती बारले, भिलाई ने पंथी नृत्य की ऊर्जापूर्ण प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। रमादत्त जोशी, रायपुर की नाचा-गम्मत की प्रस्तुति ने हास्य, मनोरंजन और लोकनाट्य के रंगों से कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया।

तीन दिनों तक चले लोकरंग पर्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों की लोकसंस्कृति, लोकगायन और लोकनृत्य की विविध परंपराओं को मंच मिला। अंतिम दिन सरहुल, करमा, आदिवासी लोकगीत, पंथी और नाचा-गम्मत जैसी प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान उसकी विविध लोकपरंपराओं में निहित है। कार्यक्रम में संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे, छत्तीसगढ़ के कवि मीर अली मीर, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार दीपेंद्र दीवान, साहित्यकार विजय मिश्रा, फिल्म बोर्ड की सदस्य मती प्रसन्ना अवस्थी तथा समाजसेवी उदयभान चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। लोकरंग पर्व का अंतिम दिन दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की विविधता और जीवंतता को करीब से अनुभव करने का अवसर बना।

कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। आयोजन ने एक ओर जहां लोककलाकारों को सम्मानजनक मंच उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की लोकपरंपराओं को सहेजने, संवारने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सार्थक संदेश दिया।

लोककलाओं को मंच देना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी : डॉ. कन्नौजे

लोकरंग पर्व के समापन अवसर पर संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुदूर जनजातीय अंचलों सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्थानीय कलाकारों ने अपनी-अपनी लोककलाओं की शानदार प्रस्तुतियां दीं। ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रोत्साहन और सम्मानजनक मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकरंग पर्व जैसे सांस्कृतिक आयोजन छत्तीसगढ़ की समृद्ध और सुघर लोकसंस्कृति को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य और पारंपरिक कलाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ती है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलने के साथ ही विलुप्त होती लोकविधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्रोत्साहन मिलता है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिलेट्स की उन्नत खेती सीखेंगे जशपुर के किसान

कृषि स्थायी समिति के सभापति गेंद बिहारी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कृषक दल को गुमला किया रवाना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जशपुर जिले में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर कृषक भ्रमण-सह-मिलेट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के किसानों का दल मिलेट्स की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला (झारखण्ड) रवाना हुआ।

कृषक दल को जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति, जिला पंचायत जशपुर के सभापति श्री गेंद बिहारी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जशपुर की जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां मिलेट्स की खेती के लिए अनुकूल हैं। जिले में रागी, कोदो और कुटकी जैसे पौष्टिक अनाजों की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। आधुनिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन व्यवस्था को अपनाकर किसान मिलेट्स की खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तकनीकी जानकारियों को गंभीरता से सीखकर अपने खेतों में अपनाने तथा इनका लाभ गांव के अन्य किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि तकनीकों का अधिक से अधिक किसानों तक विस्तार होने से जिले में मिलेट्स की खेती को नई गति मिलेगी।

कृषक भ्रमण-सह-प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मिलेट्स की उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, बीज उत्पादन, पोषक तत्व प्रबंधन तथा कीट एवं रोग प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के आधुनिक तरीकों से भी किसानों को अवगत कराया जाएगा। किसान गुमला क्षेत्र में मिलेट्स की खेती से जुड़े सफल प्रयासों और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी करेंगे।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आयोजित यह एक्सपोजर विजिट किसानों को सफल कृषि मॉडलों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे जशपुर जिले में मिलेट्स के रकबे और उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा तथा किसानों के लिए आय के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसान पारंपरिक खेती के साथ पौष्टिक एवं बाजार की दृष्टि से संभावनाशील फसलों की उन्नत खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

साइबर वित्तीय अपराधों की रोकथाम और विवेचना के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष पहल

यूपीआई फ्रॉड और डिजिटल साक्ष्यों की विवेचना पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। साइबर एवं डिजिटल माध्यमों से बढ़ते वित्तीय अपराधों की प्रभावी रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 'न्यू ऐज फिनांसियल क्राइम्स एंड रिस्पॉन्स रेडनेस' विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन विमतारा सभागार, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से करीब 300 पुलिस अधिकारी एवं विवेचक शामिल हुए।

कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, महानिदेशक (प्रशिक्षण) जी.पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपांशु काबरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला की प्रमुख विशेषता वास्तविक प्रकरणों पर आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण रहा। अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण एवं विश्लेषण, डिजिटल फुटप्रिंट की पहचान तथा वित्तीय लेन-देन की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने की तकनीकों की जानकारी दी गई। पीड़ित से शुरू होकर बैंक खाते, म्यूल अकाउंट, लेन-देन की श्रृंखला और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। इससे साइबर अपराध के पीछे सक्रिय व्यक्तियों एवं नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की विवेचना क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर एवं प्रकरण चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों एवं विवेचकों ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञ द्वारा इन मामलों में आधुनिक तकनीकों एवं प्रभावी विवेचना प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग और वैज्ञानिक विवेचना क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही।

'स्वर्णिम समय' में कार्रवाई पर विशेष जोर

कार्यशाला में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 'स्वर्णिम समय' के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि शिकायत प्राप्त होते ही संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान, धनराशि को रोकने तथा संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ तत्काल समन्वय की कार्रवाई किस प्रकार की जाए। त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से ठगी की राशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने तथा पीड़ित को राहत दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

साइबर अपराध के बदलते स्वरूप पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण

कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ डॉ. रक्षित टंडन ने पुलिस अधिकारियों को साइबर एवं वित्तीय अपराधों के लगातार बदलते स्वरूप तथा आधुनिक विवेचना तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध, म्यूल बैंक खाते, फर्जी पहचान एवं वेरिफिकेशन, यूपीआई एवं इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड आधारित धोखाधड़ी तथा रिमोट डिवाइस कंट्रोल जैसे साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि साइबर अपराधों की विवेचना में तकनीकी जानकारी के साथ समय पर कार्रवाई, डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण और विभिन्न वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पुनर्वास नीति से बदली रानू राम की जिंदगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कभी माओवादी संगठन से जुड़े ग्राम ठोटी मड़ानार पंचायत मुँगवाल निवासी रानू राम नेताम ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और सामान्य जीवन की राह अपना ली है। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रानू राम ने माओवादी संगठन से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सुरक्षित वातावरण में रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला।

आत्मसमर्पण के बाद रानू राम नेताम पुनर्वास केंद्र में रहकर अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इसी दौरान उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वाहन चलाने की बारीकियां सीखीं और सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। रानू राम बताते हैं कि अब वे पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसके बाद रानू राम को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार का अवसर मिला और वर्तमान में वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं।

आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही बंदियों की गणेश प्रतिमाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों ने मिट्टी से तैयार की 500 पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएंकेंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों ने मिट्टी से तैयार की 500 पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएं

गणेशोत्सव के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रायपुर के बंदियों ने आस्था, रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। आगामी गणेशोत्सव के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों द्वारा प्राकृतिक मिट्टी से लगभग 1 से 2 फीट आकार की 500 पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएं तैयार की गई हैं।

इन प्रतिमाओं की खासियत यह है कि इनके निर्माण में प्राकृतिक मिट्टी एवं रंगों का उपयोग किया गया है तथा प्रतिमाओं में तुलसी सहित विभिन्न पौधों के बीज भी डाले गए हैं।

गणेशोत्सव के पश्चात इन प्रतिमाओं का विसर्जन किए जाने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप लेंगे। इस प्रकार ये प्रतिमाएं धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित संदेश को भी जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगी।

केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों द्वारा विभिन्न कौशल विकास एवं उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में लगभग 10 बंदियों ने अत्यंत लगन, मेहनत और रचनात्मकता के साथ भगवान श्री गणेश की इन आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया है। यह पहल बंदियों के कौशल विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें समाजोपयोगी एवं पर्यावरण हितैषी गतिविधियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास है। मिट्टी की प्रतिमाओं में बीजों का समावेश इस कार्य को और विशेष बनाता है।

हम सभी को मिलकर कोरबा को पूर्ण साक्षर जिला बनाना है - मंत्री लखन लाल देवांगन

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला साक्षरता विभाग, कोरबा द्वारा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय साक्षरता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन साक्षर बनें, सशक्त बनें एवं उल्लास से उज्ज्वल भविष्य की ओर की थीम पर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने के साथ उनमें जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम, आबकारी तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। साक्षरता व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने के साथ दैनिक जीवन में बैंकिंग लेन-देन, शासकीय योजनाओं और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सही ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। साक्षर व्यक्ति ठगी और धोखाधड़ी का शिकार होने से भी काफी हद तक बच सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल पढ़ना-लिखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल रूप से भी जागरूक और साक्षर होना जरूरी है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा जिला विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। साक्षरता के क्षेत्र में भी जिले को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 27 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के बाद कोरबा पूर्ण साक्षर जिला बनने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कोरबा को पूर्ण साक्षर जिला बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे साक्षरता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं और अपने आसपास तथा परिवार के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विकसित छत्तीसगढ़-2047 के लक्ष्य के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने के साथ शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकता है और समाज के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है।कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि साक्षरता से व्यक्ति में जागरूकता आती है और रूढ़िवादिता दूर होती है। आज के डिजिटल दौर में डिजिटल साक्षरता भी बेहद जरूरी है। किसान, व्यापारी, पशुपालक और अन्य वर्ग के लोग जितने अधिक साक्षर होंगे।

खेल प्रतिभाओं को तराशने जिला प्रशासन की पहल खेल संघों से साझा रोडमैप तैयार करने पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। जिले की खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा खेल गतिविधियों को व्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला स्तरीय खेल संवर्धन एवं विकास संबंधी बैठक आज जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न खेल संघों एवं खेल क्लबों के पदाधिकारियों ने सहभागिता करते हुए खेलों के विकास, खिलाड़ियों की आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए समग्र खेल कैलेंडर तैयार करने, खेल संघों एवं क्लबों के पंजीयन को व्यवस्थित करने, खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सामग्री एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने तथा उन्हें नियमित प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं से जोड़ने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करने और विभिन्न खेल संघों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बैंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

जय भानुशाली संग तलाक पर पहली बार बोलीं माही विज

'बिग बॉस 20' में ईशा रिखी से कही ये बात

'बिग बॉस 20' में माही विज ने हाल ही में ईशा रिखी से बात करते हुए तलाक को लेकर ऐसी बात कह दी जिसके बाद लोग उनकी बातों पर काफी हंस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शुरुआत होते ही घर के अंदर रिश्तों, निजी जिंदगी और विवादों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शो के पहले ही एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस माही विज ने कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माही ने घर में मौजूद ईशा रिखी और बॉक्सर मैरी कॉम की निजी जिंदगी से जुड़े तलाक के मुद्दे को बातचीत में लाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस सीजन को 'डिवोर्स स्पेशल' तक कह दिया।

माही ने खुद को भी बातचीत में शामिल किया

दरअसल, घर में बातचीत के दौरान माही विज से उनकी निजी जिंदगी और मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात करने से परहेज किया। बाद में ईशा रिखी के साथ बातचीत में माही ने बताया कि उन्हें गॉसिप से जुड़े विषयों पर चर्चा करना पसंद है।

बातों-बातों में उन्होंने घर में मौजूद उन महिलाओं का जिक्र किया जिनकी जिंदगी में शादी के बाद अलगाव आया है। माही ने खुद को, ईशा और मैरी कॉम को एक साथ रखते हुए कहा कि घर में तीन ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत का दौर चल रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने इसे 'डिवोर्स स्पेशल' और अपनी 'दूसरी पारी' जैसा बताया।

ईशा रिखी ने जताई नाराजगी

माही ने ईशा से यह भी जानना चाहा कि आखिर उन्होंने 'बिग बॉस' में आने का फैसला क्यों किया। ईशा ने बताया कि वह हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश करती रही हैं और चाहती हैं कि लोग उन्हें किसी रिश्ते के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान से जानें।

हालांकि, बाद में जब माही ने मैरी कॉम के तलाक को लेकर सवाल किया तो मैरी ने इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद माही ने कहा कि किसी पूर्व साथी के बारे में केवल नकारात्मक बातें करना जरूरी नहीं है और रिश्ते में अच्छी यादें भी हो सकती हैं। इस पर ईशा नाराज होती नजर आईं और उन्होंने सवाल किया कि जब सामने वाला व्यक्ति इस विषय पर बात नहीं करना चाहता तो बार-बार उसी मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है।

माही विज और जय भानुशाली की शादी

माही विज और अभिनेता जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। दोनों ने साथ मिलकर परिवार बनाया और बच्चों की परवरिश की। कई वर्षों बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। जनवरी 2026 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अलग होने की जानकारी दी। हालांकि, दोनों अपनी बेटी की परवरिश मिलकर कर रहे हैं।

ईशा और मैरी कॉम की निजी जिंदगी भी चर्चा में

ईशा रिखी की शादी रैपर बादशाह से 2026 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के अलग होने की खबर सामने आई। वहीं, भारतीय बॉक्सिंग की दिग्गज मैरी कॉम और उनके पति ओनलर ने भी 2023 में अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया था। दोनों की शादी 2005 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं।

पहले दिन से ही सुर्खियों में शो

'बिग बॉस 20' का प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ, जहां सलमान खान ने 16 कंटेस्टेंट्स का परिचय कराया। शो के शुरुआती दौर में ही टास्क, दोस्ती, बहस और निजी जिंदगी से जुड़े मुद्दों ने माहौल गर्म कर दिया है। माही विज की तलाक वाली टिप्पणी ने भी पहले एपिसोड की चर्चाओं को और बढ़ा दिया है।

सीरीज शक की रिलीज तारीख आई, लापता बच्चे की तलाश में भटकती दिखेंगी परिणीति चोपड़ा

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर डिजिटल मंच पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी रहस्य-रोमांचक श्रृंखला 'शकः ट्रस्ट नो वन' की प्रदर्शन तिथि घोषित कर दी गई है। इस श्रृंखला का निर्माण चर्चित फिल्म निर्माता सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है, जबकि इसका निर्देशन रेनसिल डी'सिल्वा ने किया है।

पहले इस श्रृंखला का नाम 'तलाश: ए मदर्स सर्च' रखा गया था, जिसे अब बदलकर 'शक: ट्रस्ट नो वन' कर दिया गया है। निर्माताओं के अनुसार, बदला हुआ नाम श्रृंखला की रहस्यमय कहानी और उसमें मौजूद संदेह के माहौल को बेहतर तरीके से दर्शाता है।

डिजिटल मंच नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला के प्रदर्शन की तारीख की घोषणा की है। मंच की ओर से श्रृंखला का पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया, शक की सुई चल पड़ी है, तारीख नजदीक आ रही है। 'शक: ट्रस्ट नो वन' को 24 सितंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स के सदस्य दर्शक देख सकेंगे। श्रृंखला की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी और तब से परिणीति चोपड़ा के प्रशंसकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई थी।

'शक: ट्रस्ट नो वन' की कहानी एक मां और उसके नौ साल से लापता बच्चे की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है। बच्चे के अचानक गायब होने के बाद मां उसकी तलाश में जुटती है। इस दौरान उसके सामने कई ऐसे सवाल और रहस्य सामने आते हैं, जो कहानी को रहस्य और रोमांच से भर देते हैं। श्रृंखला में परिणीति चोपड़ा के अलावा ताहिर राज हुसैन, सोनी राजदान, जेनिफर विंगेट, व्यास सुमित और हर्लिन सेठी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

इस श्रृंखला का निर्माण सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है। वह भविष्य में दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी के जीवन पर आधारित जीवनीपरक फिल्म भी लेकर आने वाले हैं। वहीं 'शक: ट्रस्ट नो वन' का निर्देशन रेनसिल डी'सिल्वा ने किया है, जो रहस्य और गंभीर विषयों को पर्दे पर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

परिणीति चोपड़ा की डिजिटल मंच पर वापसी और रहस्य से भरपूर कहानी के कारण 'शक: ट्रस्ट नो वन' को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। अब 24 सितंबर को इसके प्रसारण के बाद यह देखना होगा कि श्रृंखला दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

'तमीज में रहकर भी हंसाया जा सकता है'

कैलाश खेर का फूटा समय रैना पर गुस्सा, बिहारी- कश्मीरी पंडित के चुटकुलों पर बोले

कॉमेडियन समय रैना और उनका फेमस शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' फिर विवादों में आ गया है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में बिहार और कश्मीर पर विवादित टिप्पणी की गई थी। जिस पर अब बवाल मच गया है और इसी मुद्दे पर कैलाश खेर ने भी अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कॉमेडियन और पब्लिक में रहने वाले लोगों को अपनी मर्यादा में रहने की सख्त हिदायत दी है।

कैलाश खेर ने समय रैना और शेरेन वर्मा को लेकर क्या कहा?

जब कैलाश खेर से समय रैना और कॉमेडियन शेरोन वर्मा के बीच हुए तंज भरे संवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संगीत का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी और कहा कि रचनात्मकता का मतलब मर्यादाएं तोड़ना नहीं होता। कैलाश खेर ने कहा, देखिए अगर मैं आपको संगीत के बारे में समझाऊं, तो संगीत सिर्फ एक धुन नहीं है। बुनियादी बातों में गलती करने से आपकी कला अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाली चीज में बदल जाती है।

इंसान को चैतन्य और तमीज में रहना चाहिए

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कैलाश खेर ने कहा कि हर व्यक्ति को बात करते समय शिष्टता और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, हर इंसान को जागरूक होकर ही रहना चाहिए, तमीज में रहना चाहिए। तमीज से सब बात करें, तो सबको इतना तो पता ही है कि कैसे जीना है, कैसे हंसाना है और कैसे किसी का दिल जीतना है। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना भी लोगों को हंसाया जा सकता है और उनका दिल जीता जा सकता है।

'प्रसिद्धि के साथ आती है आलोचना'

सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे करियर का जिक्र करते हुए कैलाश खेर ने कहा कि उन्होंने हमेशा विनम्र रहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, जब आप सफल होते हैं, तो आलोचक होंगे, नफरत करने वाले होंगे और ईर्ष्यालु लोग भी होंगे।

क्या था समय रैना और शेरोन वर्मा के बीच का विवाद?

यह पूरा विवाद 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2' के उस एपिसोड से शुरू हुआ था जहां, पैनलिस्ट के रूप में अर्चना पूरन सिंह भी मौजूद थीं। वहीं, शेरोन वर्मा और शो के होस्ट समय रैना के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। शो के दौरान समय रैना ने शेरोन वर्मा के बिहारी मूल और काम के लिए पलायन करने वाले लोगों पर मजाक बनाया था। जवाब में शेरोन ने समय की कश्मीरी पहचान पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा है।

सुष्मिता सेन से पहले ये एक्टर था सीरीज के लिए पहली पसंद, एक आइडिया ने बदल दी पूरी कास्टिंग

प्रोड्यूसर और क्रिएटर कार्तिक निशानदार ने खुलासा किया है कि 'ताली' के लिए सुष्मिता सेन को कास्ट करने से पहले दूसरे एक्टर को अप्रोच किया गया था। हालांकि, बाद में मेकर्स ने ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्रीगौरी सावंत का किरदार सुष्मिता सेन से करवाने का फैसला किया।

हमें एक मां चाहिए थी

इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में कार्तिक ने 'ताली' में श्रीगौरी सावंत के किरदार के लिए सुष्मिता सेन को चुनने की वजह बताई। उन्होंने सुष्मिता की अपने किरदार के प्रति मेहनत और लगन के बारे में भी बात की। कार्तिक ने बताया कि 'ताली' में सुष्मिता सेन को कास्ट करते समय मेकर्स इस किरदार को ट्रांसजेंडर किरदारों की पिछली स्क्रीन प्रस्तुतियों से थोड़ा अलग दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'जब हम 'ताली' के लिए सुष्मिता को कास्ट कर रहे थे, तो हमें एक मां चाहिए थी। हम चाहते थे कि उस किरदार को एक महिला निभाए, क्योंकि कहानी एक मां के अधिकारों और उसकी भावनाओं के बारे में है। सुष्मिता इस किरदार के लिए बिल्कुल सही थीं।

पहले इस एक्टर को किया था अप्रोच

कार्तिक ने बताया कि सुष्मिता का नाम पहले से ही उनके दिमाग में था, लेकिन इस रोल के लिए सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी से संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा, 'हमारे दिमाग में सुष्मिता हमेशा से थीं और हमने करीब 15-20 साल पहले उनके साथ काम भी किया था। लेकिन सबसे पहले हमने नवाज को अप्रोच किया था। हमने नवाज से बात की। फिर एक दिन अर्जुन सिंह ने कहा, 'कार्तिक, अगर हम इस किरदार के लिए किसी महिला को कास्ट करें तो? हर कोई ट्रांसजेंडर किरदार के लिए एक पुरुष को कास्ट कर रहा है।' कार्तिक ने बताया कि यह आइडिया पूरी टीम को तुरंत पसंद आ गया। इसके बाद सुष्मिता से संपर्क किया गया।

मेकअप के दौरान कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां

कलर करेक्टर का इस्तेमाल मेकअप को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की असमानताओं को छिपाने और एक समान रंग देने में सहायक होता है। हालांकि, कई महिलाएं कलर करेक्टर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पातीं और इससे उनका मेकअप बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें महिलाएं कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते समय करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

गलत रंग का चयन करना

कलर करेक्टर का सही रंग चुनना बहुत जरूरी होता है। कई महिलाएं अपने त्वचा के रंग को ध्यान में रखे बिना ही किसी भी रंग का चयन कर लेती हैं, जिससे उनका मेकअप अच्छा नहीं दिखता।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो पीच या नारंगी शेड बेहतर होते हैं, जबकि गहरे त्वचा रंग वाली महिलाओं के लिए हरा या पीला शेड उपयुक्त होते हैं। सही रंग चुनने से आपका मेकअप ज्यादा निखरता है।

ज्यादा मात्रा में उपयोग करना

कलर करेक्टर का ज्यादा उपयोग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। कुछ महिलाएं यह सोचती हैं कि ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से उनकी समस्याएं बेहतर तरीके से छिपेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता।

ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से चेहरा भारी दिखने लगता है और प्राकृतिक रूप से छिपी हुई समस्याएं उभरकर सामने आने लगती हैं।

इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कलर करेक्टर का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप स्वाभाविक लगे।

गलत जगह पर लगाना

कलर करेक्टर लगाने की जगह भी अहम होती है। कई महिलाएं बिना सोचे-समझे कहीं भी कलर करेक्टर लगा लेती हैं, जिससे उनका पूरा लुक बिगड़ जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो वहां पीच या नारंगी शेड लगाएं, ताकि वे छिप जाएं। इसी तरह अगर आपकी त्वचा पर लाल धब्बे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए सही जगह पर सही रंग का उपयोग करें।

गलत तरीके से मिलाना

कलर करेक्टर को सही तरीके से मिलाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह त्वचा में पूरी तरह मिल जाए और अलग से दिखाई न दे। कई महिलाएं इसे ठीक से नहीं मिलातीं, जिससे उनका मेकअप बनावटी लगता है।

सही तरीके से मिलाने के लिए पहले उंगलियों या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से फैलाएं, फिर ब्रश की मदद से सेट करें।

इससे आपका मेकअप प्राकृतिक दिखेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा।

बेस मेकअप के साथ मेल न खाना

कलर करेक्टर और बेस मेकअप का मेल होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा एक समान दिखे। कई बार महिलाएं अलग-अलग ब्रांड या शेड का उपयोग कर लेती हैं, जिससे उनका चेहरा असंगत दिखता है।

हमेशा एक ही ब्रांड और शेड का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप पूरी तरह संतुलित लगे।

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकती हैं और हर मौके पर खूबसूरत दिख सकती हैं।

'टॉक्सिक' में महिलाओं की भूमिका पर उठे सवाल, संजीदा शेख ने तोड़ी चुप्पी- 'मैं उसे जाने देती हूं'

यश स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' रिलीज के बाद से ही चर्चा में है। फिल्म को जहां दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं, वहीं इसके हिंसक कंटेंट और फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी में भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब फिल्म में यश और नयनतारा की मां का यंग वर्जन निभाने वाली संजीदा शेख ने फिल्म को मिल रही आलोचना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

संजीदा ने कहा कि किसी भी फिल्म को लेकर लोगों की अपनी राय हो सकती है और वह रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती हैं। हालांकि, अगर किसी प्रतिक्रिया में सिर्फ शोर है, तो वह उस पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहतीं।

'कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हमेशा स्वागत है'

संजीदा शेख ने बताया कि किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद वह उसके नतीजे के बजाय पूरे सफर पर ध्यान देती हैं। 'टॉक्सिक' को लेकर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा कि हर दर्शक फल्म को अपने नजरिए से देखता है और उसकी राय कलाकारों से अलग हो सकती है। एक्ट्रेस के मुताबिक, वह फिल्म का हिस्सा बनकर खुश हैं और उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। संजीदा ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हमेशा वेलकम है, लेकिन अगर सिर्फ शोर हो रहा है, तो मैं उसे जाने देती हूं।

सिर्फ3 दिन में शूट किया था अपना हिस्सा

संजीदा शेख का 'टॉक्सिक' में रोल छोटा जरूर था, लेकिन कहानी के लिहाज से अहम था। उन्होंने फिल्म में यश और नयनतारा के किरदारों की मां का यंग वर्जन निभाया है। उनके किरदार के सीन कहानी के फ्लैशबैक वाले हिस्से में आते हैं।

संजीदा ने बताया कि फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उन्हें संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में उनका एक सीन देखने के बाद संपर्क किया था। हालांकि, संजीदा पहले से 'टॉक्सिक' के बारे में जानती थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें इस फिल्म में रोल मिल सकता है। एक्ट्रेस ने फिल्म साइन करने से पहले यह भी पूछा था कि क्या उनके किरदार के पास परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। उनका कहना था कि वह ऐसा रोल नहीं करना चाहती थीं जो फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट के बीच कहीं खो जाए।

फिल्म में संजीदा के सीन अलग समय-काल में दिखाए गए हैं। इसी वजह से शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात यश या नयनतारा से नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वह फिल्म में उनके किरदारों के बचपन का रोल निभाने वाले बच्चों के साथ शूट कर रही थीं। संजीदा ने कहा कि वह सेट पर गईं, अपना हिस्सा शूट किया और टीम से उन्हें अच्छी एनर्जी मिली। ट्रेलर से पहले उनकी कास्टिंग को सीक्रेट रखा गया था, इसलिए फिल्म में उनका आना दर्शकों के लिए भी सरप्राइज रहा।

खास-खबर

पीडीएस के तहत दो माह सितंबर और अक्टूबर का चावल वितरण जारी

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के सभी 14 हजार 186 उचित मूल्य दुकानों में दो माह सिंतबर और अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न आबंटन जारी कर दिया गया है। इन उचित मूल्य दुकानों में से 9,356 (66 प्रतिशत) दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण हो गया है तथा राशनकार्डधारियों को उक्त दो माह के चावल वितरण जारी है।
राशनकार्डधारी कोई भी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल 30 सितंबर तक ले सकते है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दो माह के खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण का कार्य प्रचलित है। 08 सिंतबर 2026 तक खाद्यान्न 2.62 लाख राशनकार्डधारियों द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया गया है। 30 सिंतबर 2026 तक 02 माह का खाद्यान्न वितरण पूर्ण करने हेतु सभी जिलों को निर्देश दिए गए है। राज्य शासन द्वारा दो माह के खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की नियमित निगरानी/मॉनिटरिंग की जा रही है।

देवगढ़ की रुकमणी ने हुनर को बनाया रोजगार

रायपुर। देवगढ़ की रुकमणी ने हुनर को बनाया रोजगारकभी गृहिणी के रूप में परिवार संभालने वाली रुकमणी आज सीमेंट से मंदिर और सजावटी सामग्री तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने मेहनत और हुनर के दम पर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने समूह के माध्यम से बचत की और ऋण लेकर अपने हुनर को रोजगार का रूप दिया। आज इस काम से उन्हें हर महीने करीब 45 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम देवगढ़ की रुकमणी कुंवर ने बिहान योजना के तहत गठित समूह से जुड़ीं। समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने नियमित बचत शुरू की।

शिक्षकों के नवाचारों से संवरेगी जिले की शिक्षा

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्ञानदीप व शिक्षा दूत से पुरस्कृत शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों एवं सफल शैक्षणिक गतिविधियों के अनुभव साझा किए गए। शिक्षकों के अनुभवों और नवाचारों के आधार पर जिले में शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर संवाद, कार्यशाला एवं कार्ययोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालयों में शिक्षा को रोचक, प्रभावी और बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी।

राजनांदगांव में प्रस्तावित गैस आधारित फर्टिलाइजर प्लांट से औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगी नई गति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके रायपुर स्थित निवास पर आत्मीय भेंट की।

इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राजनांदगांव में गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रस्तावित गैस आधारित फर्टिलाइजर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 तथा प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजनांदगांव में गेल (इंडिया) लिमिटेड का प्रस्तावित गैस आधारित फर्टिलाइजर प्लांट क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ सहायक उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इससे राजनांदगांव सहित आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में नई संभावनाओं वाले उद्योगों के विस्तार के साथ आधुनिक तकनीक और उच्च मूल्य आधारित विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आधुनिक विनिर्माण के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं और निवेश के लिए नई संभावनाएं बनी हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में आने वाला निवेश स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि का माध्यम बने। राजनांदगांव की प्रस्तावित फर्टिलाइजर परियोजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

शिक्षकों के मार्गदर्शन और जनसेवा से ही संभव है समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास- मंत्री टंक राम वर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा आज नेवरा स्थित पी. एम श्री कन्या शाला में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व व कृतित्व को नमन करते हुए कहा कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने के संस्कार भी गढ़ते हैं। मस्तिष्क और बुद्धि के सर्वांगीण विकास के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है।

प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक युग तक, जब भी समाज या राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां आई हैं, गुरुजनों ने ही सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शेड, बाउंड्रीवॉल, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं।

शिक्षक सम्मान समारोह और अपने गुरुजनों से मुलाकात का स्मरण करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि गुरुजनों का सम्मान हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का मूल आधार है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवादों के निपटारे और सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका होती थी। वर्तमान तकनीकी युग में व्यस्तता भले ही बढ़ी है, लेकिन समाज को समय देकर ग्रामीण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इस दौरानमंत्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की छवि सुधारने के लिए किए गए क्रांतिकारी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैन्युअल से ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करते समय हुई त्रुटियों के जल्द निपटारे हेतु अधिकारों का विस्तार कर तहसीलदारों को भी शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार अब कमिश्नर के स्थान पर सीधे जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए 5 डिसमिल से कम जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, जबकि फर्जी रजिस्ट्री रोकने हेतु तहसील कार्यालयों को पंजीयन कार्यालय से ऑनलाइन जोड़कर रजिस्ट्री के समय ओटीपी अनिवार्य किया गया है। अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद ऑटोमैटिक नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी और किसानों को किसान पुस्तिका के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटकर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। भू-स्वामी अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवारा कर सकते हैं। वहीं, भारतमाला जैसी बड़ी परियोजनाओं में भू-माफियाओं के अनुचित लाभ को रोकने के लिए अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्र की खरीद-बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है, ताकि वास्तविक किसानों को पारदर्शी मुआवजा मिल सके।

उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु 40 गांवों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही 100 गांवों के तालाबों में पक्के चबूतरों का निर्माण, 40 गांवों में महतारी सदन का निर्माण और सरस्वती शिशु मंदिर जैसी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण स्वीकृत कराए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि जनसेवा के इन कार्यों में वरिष्ठों और गुरुजनों का मार्गदर्शन सदैव सर्वोपरि रहेगा।

श्रमिक की बेटी अब रायपुर के कांगेर वैली स्कूल में करेगी पढ़ाई

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मेहनत करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना अब उनके भविष्य को नई दिशा दे रही है। इसी योजना के तहत महासमुन्द जिले के विकासखंड बागबाहरा के ग्राम फुलवारी निवासी पूनम कुमार यादव की बेटी प्रियांशी यादव का चयन राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित कांगेर वैली स्कूल में हुआ है। वह कक्षा 6वीं से 12वीं तक वहां नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करेगी।

बेटी के चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। पूनम कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतने प्रतिष्ठित और महंगे स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना उनके जैसे श्रमिक परिवारों के लिए उम्मीद और अवसर लेकर आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए भी अवसर उपलब्ध करा रही है।

श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाकर गुणवत्तापूर्ण एवं नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना है। महासमुन्द जिले की पूनम कुमार यादव की बेटी का चयन इसी दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण है, जहां श्रमिक परिवार की बेटी अब बेहतर शिक्षा के जरिए अपने सपनों को नई उड़ान देने की तैयारी कर रही है।

सोशल मीडिया की ताकत से दुनिया तक पहुंचेगी धमतरी की खूबसूरती

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जिले की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, धार्मिक- सांस्कृतिक विरासत और साहसिक पर्यटन को वैश्विक पटल पर उभारने के लिए बरदिहा रिसोर्ट में 'मॉनसून क्रिएटर मीट-अप 2026' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से धमतरी की लोक-संस्कृति, खानपान और पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाने की रणनीतियों पर मंथन किया।

इस दौरान कलेक्टर धमतरी ने कहा कि वर्तमान दौर डिजिटल मीडिया का है। क्रिएटिव और जिम्मेदार कंटेंट के जरिए किसी भी अनजान जगह या स्थानीय प्रतिभा को बेहद कम समय में दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। उन्होंने गंगरेल बांध, पहाड़ियों, वनों, आदिवासी संस्कृति, ग्रामीण जीवन और 'फूड, फेथ एंड कल्चर' को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभारने की आवश्यकता जताई। धमतरी जिले में पर्यटन और डिजिटल पहल के लिए ?क्रिएटर्स को नई सुविधाएं मिलेगी। प्रशासन द्वारा कुरुद में एक समर्पित 'यूट्यूब रूम' तैयार किया जा रहा है, जबकि धमतरी में भी ऐसी ही डिजिटल सुविधा विकसित करने की योजना है।

पर्यटन के विकास से होम-स्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। जिले में सुनियोजित और समग्र विकास के लिए पर्यटन समिति का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सकारात्मक पहल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में छत्तीसगढ़ी भाषाविदों ने भेंट कर छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के संबंध में चर्चा की।

भाषाविदों ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ी भाषा की प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा, व्याकरण, शब्दकोश एवं मानकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश की राजभाषा एवं प्रमुख संपर्क भाषा है और लगभग डेढ़ करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं। राज्यपाल श्री डेका ने स्वयं पहल करते हुए इस विषय पर सार्थक चर्चा की। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोश एवं अन्य संदर्भ सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया जाएगा। इसके लिए विषय के विद्वानों एवं विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी और सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यपाल ने इस संदर्भ में असमिया और बोडो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का उदाहरण भी दिया।

भाषाविदों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी में 15 वीं शताब्दी से साहित्य सृजन की समृद्ध परंपरा रही है। कविता, खंडकाव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना एवं पत्रकारिता सहित विभिन्न विधाओं में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण वर्ष 1890 में तथा पहला शब्दकोश वर्ष 1939 में तैयार हुआ। वर्ष 1924 में पहला छत्तीसगढ़ी उपन्यास 'हीरू के कहिनी' प्रकाशित हुआ।

पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल से हस्तलिखित छत्तीसगढ़ी पत्रिका 'दुलरवा' का प्रकाशन भी किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छत्तीसगढ़ी का अध्ययन कराया जा रहा है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा पहली से आठवीं तक के पाठ्यक्रम में भी छत्तीसगढ़ी को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।

इस अवसर पर भाषाविद् डॉ. चित्ररंजन कर, डॉ. सुधीर शर्मा, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार शीलकांत पाठक एवं श्रीमती अर्चना पाठक उपस्थित थीं।

आस्था, परंपरा और भव्यता के रंग में सजेगा ऐतिहासिक बस्तर दशहरा

75 दिवसीय पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का संकल्प, बलराम मांझी बने नए उपाध्यक्ष

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम विश्वप्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व 2026 इस वर्ष भी पूरी भव्यता, आस्था और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियों, पूजा विधान, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न आयोजनों को लेकर मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में बस्तर दशहरा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप ने की।

बैठक में बस्तर राजपरिवार के कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना, दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी के पुजारी जिया बाबा सहित समस्त मांझी-चालकी, मेंबर-मेंबरीन, पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं टेम्पल स्टेट समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ हुई। इसके बाद बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कराया गया। बचेली परगना के श्री बीरो मांझी ने श्री अर्जुन मांझी के नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि सोनाबाल परगना के श्री समुन्द मांझी ने श्री बलराम मांझी के नाम का प्रस्ताव किया। सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें स्पष्ट बहुमत के आधार पर बलराम मांझी को बस्तर दशहरा समिति का नया उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बलराम मांझी ने देवसराय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव दिए।

बस्तर राजपरिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव ने बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1423 से निरंतर चली आ रही यह परंपरा मैसूर और कुल्लू दशहरा से भी प्राचीन है। उन्होंने बस्तर दशहरा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए सामूहिक प्रयास और साझा संकल्प को दोहराया। उन्होंने मावली परघाव के लिए संबंधित स्थलों एवं मार्गों की विशेष साफ-सफाई, देवी-देवताओं और आंगा देव के सम्मानपूर्वक आगमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही मांझी-चालकी से पर्व के दौरान पारंपरिक वेशभूषा एवं पगड़ी धारण करने का आग्रह किया।

श्री भंजदेव ने मेंबर-मेंबरीन के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मेंबरीन के मासिक मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी दशहरा समिति के समक्ष रखा। कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बस्तर दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में मौजूद मांझी-चालकी, पुजारी, मेंबर-मेंबरीन और समिति के सदस्यों ने भी विभिन्न पूजा विधान एवं आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव दिए।

केवल पर्व नहीं, विश्व की अनूठी सांस्कृतिक विरासत

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और विश्व की अनूठी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने पर्व की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए एनएमडीसी प्रबंधन से सीएसआर मद के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये की स्थायी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग करने की बात कही। बस्तर दशहरा के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से सकारात्मक चर्चा हुई है। सांसद ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाले इस विशिष्ट पर्व की मौलिकता और परंपरागत स्वरूप को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

1.21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

बैठक में दशहरा समिति के सचिव एवं तहसीलदार ने बस्तर दशहरा पर्व के लिए एक करोड़ 21 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया। उन्होंने पर्व के दौरान संपन्न होने वाले विभिन्न पूजा विधानों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी समिति के सदस्यों को दी। बैठक में पूजा स्थलों, मार्गों, देवस्थलों, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पर्व की विशिष्ट परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के साथ आयोजन को सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

देशव्यापी साक्षरता पखवाड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन

महासमुंद। देशव्यापी साक्षरता पखवाड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यक्रम से जुड़े व्यक्ति, स्वयंसेवी शिक्षक एवं उल्लास के शिक्षार्थी को शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उल्लास साक्षरता पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान, उत्कृष्ट स्वयंसेवी शिक्षकों का सम्मान, पुस्तिका/साहित्य का विमोचन, उल्लास हेतु शपथ ग्रहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, माजदा वाहन के साथ साउंड सिस्टम जब्त

भिलाई। सेक्टर -4 चौक पर रात को अत्याधिक तेज आवाज में डीजे बजाना भारी पड़ गया। कुछ लोग माजादा वाहन में डीजे के साथ नाच गा रहे थे। शोर इतना था कि आसपास के घरों में रहने वाले तक सहम गए। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर तनिष चौधरी द्वारा माजदा वाहन क्रमांक सीजी 07 एलएक्स 8552 में 06 नग डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में संचालन करना पाया गया। डीजे संचालन के संबंध में वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर कोई अनुमति नहीं होना लिखित रूप में बताया गया। इस मामले में भट्ठी पुलिस ने त्वरित कार्रवई करते हुए साउंड सिस्टम के साथ माजदा वाहन को भी जब्त कर लिया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत पाए जाने पर पुलिस द्वारा मौके से माजदा वाहन, 06 नग डीजे साउंड बॉक्स एवं 01 नग एम्पलीफायर जप्त कर इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार किया गया।

जनमाष्टमी मेला दिखाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग को जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने युवक कोरबा ले गया। वहां होटल में रुककर उसके साथ रेप किया। कोतरा रोड क्षेत्र में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 साल की बेटी 4 सितंबर को बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति के बहला-फुसलाकर उसे भगा ले जाने की आशंका जताई। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों और सहेलियों से पूछताछ की। नाबालिग के कोरबा जिले के अनूप साह के संपर्क में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने तत्काल संदेही को किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में पकड़ा। उसके साथ गुम नाबालिग भी मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(द्व) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

शराब के लिए पैसा नहीं देने पर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। भिलाई शराब पीने के लिए महिला से रुपए की मांग करने वाले आदतन अपराधी को थाना खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सुशील उर्फ चुग्गे ने महिला से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की, महिला द्वारा रुपए देने से मना करने पर आरोपी ने महिला के साथ अश्लील गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद महिला ने थाना खुर्सीपार में शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

रायपुर ग्रामीण पुलिस की समझाइश का असरः ग्रामीणों ने सौंपे चाकू, तलवार और रॉड

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब गांवों में भी दिखाई देने लगा है। तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने स्वेच्छा से 15 हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान पुलिस के सामने जमा कराया है। इनमें चाकू, तलवार, रॉड सहित अन्य सामान शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश में चल रहे अभियान में पुलिस के साथ गांवों के सरपंच और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे ग्रामीणों और पालकों को हथियार रखने से होने वाले नुकसान और नए कानून के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। लगातार जागरूकता के बाद ग्रामीण खुद आगे आकर अपने पास रखे हथियार पुलिस को सौंप रहे हैं। रायपुर ग्रामीण डीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि कई बार अचानक आए गुस्से या मामूली विवाद में हथियार का इस्तेमाल गंभीर

अपराध का कारण बन जाता है। छोटी- सी कहासुनी में चाकू, तलवार या रॉड का इस्तेमाल होने से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है या मामला जानलेवा भी हो सकता है। इसी वजह से पुलिस की ओर से बच्चों और युवाओं को हथियारों से दूर रखने के लिए पालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि घर या आसपास ऐसे हथियार न रखें, जिनका इस्तेमाल विवाद की स्थिति में नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

पुलिस की कार्रवाई के साथ ग्रामीणों का सहयोग मिलने से अभियान को मजबूती मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा स्वेच्छा से हथियार जमा कराना पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गांव-गांव में सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य हथियारों से होने वाली हिंसक घटनाओं को रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित माहौल तैयार करना है।

पैसों की लालच में साइबर ठगों को बेच दिया खाता, दुर्ग में 6 आरोपी गिरफ्तार

15 हजार तक कमीशन लिए, लाखों के लेनदेन का खुलासा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी की रकम बैंक खातों में मंगाकर आगे ट्रांसफर करने वाले 6 म्यूल बैंक खाताधारकों पर कार्रवाई की है। आरोपियों पर 2 हजार से 15 हजार रुपए तक के कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, पासबुक, एटीएम, चेकबुक और सिम कार्ड दूसरे लोगों को उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस की जांच में इन खातों में लाखों रुपए से अधिक की संदिग्ध साइबर ठगी की रकम का लेनदेन सामने आया है।

कार्रवाई सुपेला, भिलाई भट्ठी, भिलाई नगर थाना और एसीसीयू की टीम ने संयुक्त रूप से की। पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधों की जांच के दौरान ठगी की रकम जिन बैंक खातों में पहुंची, उनका बैंक लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया। भिलाई भट्ठी, भिलाई नगर और सुपेला थाना क्षेत्र के कुछ खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से मिली रकम को आगे भेजने और खपाने में किए जाने की जानकारी मिली।

पासबुक, एटीएम, चेकबुक और सिम कार्ड दिए

जांच में सामने आया कि खाताधारकों ने कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों से जुड़े जरूरी दस्तावेज और साधन दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध कराए थे। इनमें पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड शामिल हैं। इन खातों में साइबर ठगी से मिली रकम जमा होने के बाद उसे दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस ने बैंक लेनदेन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

तीन थानों में की गई कार्रवाई

8 सितंबर को पुलिस ने सुपेला थाना क्षेत्र के मामले में 3, भिलाई भट्ठी थाना क्षेत्र के मामले में 1 और भिलाई नगर थाना क्षेत्र के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने या अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते एजेंटों अथवा दूसरे लोगों के जरिए साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें कमीशन दिया जाता था। खातों के साथ एटीएम, चेकबुक, पासबुक और सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते थे। इसके बाद साइबर ठगी की रकम इन खातों में मंगाकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की जाती थी।

पुलिस ने मोहन राम (50), निवासी घासीदास नगर जामुल; गजेन्द्र कुमार साहू (23), निवासी हिन्द नगर रिसाली; भीष्म लाल भारती (27), निवासी सांकरा कुम्हारी; ओम प्रकाश यादव (28), निवासी चिखली; देवरतन टंडन (39), निवासी शहीद वीर नारायण नगर खुर्सीपार और लोकनाथ वर्मा (29), निवासी सुपेला को गिरफ्तार किया है।

बैंकिंग दस्तावेज और मोबाइल जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस इन खातों में हुए लेनदेन की जानकारी के आधार पर साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

छेड़छाड़ से परेशान कॉलेज छात्रा ने खाया जहर, तीन दिन बाद मौत

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में 21 साल की कॉलेज छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर जहर खा लिया। तीन दिन तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चलने के बाद रविवार शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 17 साल के नाबालिग पर छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। युवती के पिता नहीं थे। उसके दो भाई बाहर काम करते हैं। वह अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। 12वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया था। परिजनों के मुताबिक, वह पढ़ाई में अच्छी थी।

युवती की मां और भाइयों ने आरोप लगाया कि गांव का 17 साल का नाबालिग लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। वह कॉलेज आते-जाते उसका रास्ता रोककर छेड़छाड़ करता था। साथ ही मां और भाई के नाम सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की धमकी देता था और युवती पर मिलने का दबाव बनाता था। परिजनों का कहना है कि उन्होंने नाबालिग को कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी हरकतों से युवती काफी तनाव में थी। वह परेशान होकर आत्महत्या करने की बात भी कहती थी। परेशान होकर युवती ने 3 सितंबर को चूहा मारने वाली दवा खा ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे लगातार उल्टियां होने लगीं। परिजनों ने उसे पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। शुरुआती इलाज के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां तीन दिन इलाज के बाद रविवार शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि नाबालिग की हरकतों को लेकर पहले भी थाने में मौखिक शिकायत की गई थी। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि जिला मेडिकल कॉलेज से मिले मेमो के आधार पर जिला अस्पताल चौकी में परिजनों का बयान दर्ज किया गया है।

नशे में स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवर को जेल, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद 3 दिन कारावास की सजा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस की जांच के दौरान स्कूल बस चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर ही बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की और केस न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामला 7 सितंबर का है। यातायात पुलिस दुर्ग की टीम स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच कर रही थी। इसी दौरान केपीएस कुठेला भाठा दुर्ग

की स्कूल बस की जांच की गई। बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा शराब के नशे में बस चलाते मिला।

पुलिस ने तत्काल बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की और केस न्यायालय में पेश किया। इसके अलावा धारा 184 के तहत भी कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास की सजा और कुल 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

कोर्ट ने धारा 185 के तहत चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, धारा 184 के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अगर चालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास निर्धारित किया गया है। यानी जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों धाराओं में कुल 40 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

स्कूटी और हेयर कट से पकड़ाए चोरः कुशालपुर के ज्वेलर्स में हुई थी चोरी, 4.50 लाख का माल जब्त

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कुशालपुर के न्यू नंदी ज्वेलर्स का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के चांदी के जेवर और सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों और एक नाबालिग को पकड़ा है। मुख्य आरोपी संजय चौहान आदतन चोर है।

उसके खिलाफ डीडी नगर, कोतवाली और गुढ़ियारी समेत अलग-अलग थानों में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह पहले जेल भी जा चुका है। दुकान संचालक अजय मंडल 31 अगस्त की रात 8:30 बजे दुकान बंद कर गए थे। अगले दिन सुबह 11 बजे पहुंचे तो शटर का एक ताला टूटा मिला। दुकान से चांदी के जेवर, सिक्के, कटोरी, चम्मच और गिलास चोरी हो गए थे।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुराने चोरी के मामलों में शामिल आरोपियों की गतिविधियां खंगालीं। सुराग मिलने पर संजय को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने वारदात स्वीकार कर ली। इसके बाद होरीलाल पंकज और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। आरोपियों से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल मेस्ट्रो समेत करीब 4.50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। होरीलाल सरस्वती नगर में धोखाधड़ी के एक मामले में भी फरार था।

शराब के नशे में बिना तैयारी के दिया वारदात को अंजाम वारदात वाले दिन संजय, होरीलाल और नाबालिग ने साथ में शराब पी थी। इसके बाद तीनों शहर में घूम रहे थे। मलसाय तालाब के पास ज्वेलरी शॉप देखकर उन्होंने दो-तीन बार इलाके में घूमकर रेकी की और चोरी कर ली। वारदात की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से स्कूटी की कंपनी और रंग का पता लगाया और उसके रूट के कैमरे खंगाले। फुटेज में स्कूटी चला रहे संजय के हिप्पी कट बाल दिखाई दिए। स्कूटी कबीर नगर की ओर जाती मिली तो वहां रहने वाले पुराने नकबजनी के आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। इससे संजय की पहचान हो गई। संजय और होरीलाल की दोस्ती जेल में हुई थी। वहां मारपीट के दौरान संजय ने होरीलाल की मदद की थी। इसके बाद से दोनों संपर्क में थे।

खाद की कालाबाजारी पर दो दुकानदारों को नोटिस

रकबे से ज्यादा खाद बेचने और रेट लिस्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दो दुकानों पर रकबे से ज्यादा यूरिया बेचने और रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं करने समेत कई अनियमितताएं मिलीं।

दोनों दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार को तखतपुर विकासखंड के ग्राम डोमनपुर स्थित जायसवाल ट्रेडर्स की जांच की। जांच में सामने आया कि दुकान संचालक किसानों को निर्धारित रकबे से ज्यादा यूरिया खाद बेच रहा था। यह नियमों के खिलाफ है। मामले में उर्वरक निरीक्षक एके सिन्हा ने दुकान संचालक को नोटिस

जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उर्वरक लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

रेट लिस्ट नहीं लगाने पर भी नोटिस

इसी तरह शुभम कृषि केंद्र, पाली में बिक्री दर की सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी। इस पर दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

कार्रवाई के दौरान तखतपुर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आरएल पैंकरा भी मौजूद रहे। कृषि विभाग ने खाद की बिक्री में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर के तालाब में मिला किन्नर का शव, तीन दिन से था लापता

कार सवार युवकों से आखिरी बार बातचीत, दोस्त के साथ पी शराब

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। बिलासपुर में 3 दिन से लापता किन्नर की लाश तालाब में मिली है। शहर में इससे पहले भी किन्नर की हत्या हो चुकी है। ऐसे में किन्नर समुदाय ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में डूबने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। शव करीब 72 घंटे पुराना होने के कारण डिकंपोज होना शुरू हो गया था, जिससे चोट के निशान भी स्पष्ट नहीं हो सके हैं।

घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। दरअसल, मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली की ग्राम पेंडारी स्थित मुरुम खदान से बने तालाब में मंगलवार को एक युवक की लाश

पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान किन्नर सागर पासी उर्फशैगी (28) के रूप में हुई। पुलिस की जांच और पूछताछ में पता चला है कि सागर रविवार सुबह स्कूटी लेकर घर से निकला था। इसके बाद वह एक साथी के साथ कोटा के कोरी डैम पहुंचा, जहां दोनों ने शराब पी। लौटते समय गनियारी से दोबारा शराब खरीदी और पेंडारी तालाब के पास बैठकर रात करीब 9 बजे तक शराब पीते रहे।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि तालाब के पास कार सवार दो युवक पहुंचे थे और उन्होंने सागर से सिगरेट मांगी। सागर उनके पास जाकर उनसे बातचीत करने लगा। कुछ देर बाद उसने मोबाइल बंद होने की बात कहते हुए अपना मोबाइल और स्कूटी साथी को दे दी और उससे घर जाने के लिए कहा। इसके बाद सागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

मन्नू चौक निवासी सागर पासी उर्फ शैगी साल 2019 से किन्नर समुदाय के साथ रह रहा था। इससे पहले भी सकरी क्षेत्र में किन्नर की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा किन्नरों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद भी चल रहा है। सागर तीन दिन से लापता था। ऐसे में किन्नर समुदाय ने उसकी हत्या की आशंका जताई है।

पीएम और कार सवार युवकों से पूछताछ से खुलेगा राज

एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया कि शव करीब 72 घंटे पुराना है और पानी में पड़े रहने के कारण डिकंपोज हो चुका है। ऐसे में शरीर पर चोट के निशान स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस हत्या और हादसा, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

पीएम रिपोर्ट और कार सवार युवकों से पूछताछ के बाद मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस तकनीकी जांच के साथ घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

महंगी बाइक के शौक ने बनाया चोर

कोरबा। कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। महंगी मोटरसाइकिल चलाने के शौक और पैसे की कमी के चलते तीन दोस्तों ने चोरी की योजना बनाई थी। चोरी करने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल की दूसरी चाबी बनवाने के लिए कोरबा के टीपी नगर स्थित एक दुकान पर पहुंचे थे। संयोग से जिस मोटरसाइकिल की चाबी बनवाने आरोपी पहुंचे थे, उसके मालिक का रिश्तेदार भी टीपी नगर में ही चाबी बनाने का काम करता है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मोनेन्द्र कुमार उर्फमोनू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो नाबालिग साथियों को भी संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है।

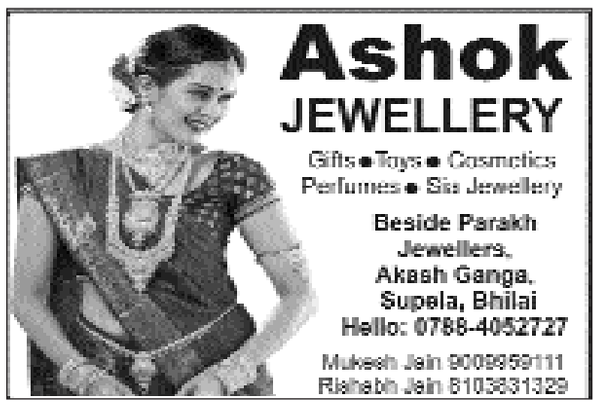

शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों में लाएं तेजी : मुख्यमंत्री

नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी लाने और शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक समय पर पहुंचे, यह अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के नगरीय निकायों में युवाओं को अध्ययन के लिए आधुनिक और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए जा रहे सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन 'नालंदा परिसर' की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन परिसरों के कार्यों में तेजी लाते हुए इन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 31 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिसरों में प्रस्तावित सीटों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की।

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को शीघ्र मिले आवास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों, निर्माण की स्थिति, आबंटन और व्यवस्थापन की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि आवासों के आवंटन एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पात्र परिवारों को शीघ्र अपने पक्के आवास का लाभ मिल सके।

चार प्रमुख शहरों में 240 ई-बसों से मजबूत होगा सार्वजनिक परिवहन: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना संबंधी कार्य मार्च 2027 से पहले पूर्ण कर ई-बसों का संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री साय ने संबंधित सभी निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बस सेवा से नागरिकों को आधुनिक, सुविधाजनक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होने के साथ पर्यावरण-अनुकूल शहरी परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

अमृत मिशन के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी, मिशन मोड में काम करने के निर्देश: मुख्यमंत्री साय ने अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता का विषय है। अमृत मिशन के लंबित कार्यों को मिशन मोड में लेते हुए तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण में उच्च गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन की दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

800 करोड़ रुपये की लागत से 8 नगरीय निकायों में सीबीजी प्लांट: बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वच्छ एवं सतत ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सतत योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं में परिणाम स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा, निर्माण की गुणवत्ता की सतत निगरानी तथा सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नागरिकों की शिकायतों का हो त्वरित और प्रभावी समाधान

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में नगरीय प्रशासन से संबंधित प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी टैक्स के पुनरीक्षण से संबंधित विषयों और नगरीय निकायों के विद्युत देयकों की भी जानकारी ली। उन्होंने नगरीय निकायों को विद्युत देयकों का नियमित रूप से प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व एवं कर संकलन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर संकलन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने की व्यवस्था विकसित की जाए।

सुनियोजित और नागरिक-केंद्रित हों प्रदेश के शहर

मुख्यमंत्री साय ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए शहरों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 14 नगर निगमों के लिए प्रारंभ की गई इस योजना के तहत मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास सहित यातायात से संबंधित आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत नगरीय विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि नगरीय निकायों के सतत, संगठित एवं नागरिक-केंद्रित विकास के लिए 'आदर्श शहर समृद्धि योजना' प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नागरिकों से सीधे जुड़ी इन सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर के प्रदर्शन की मुख्यमंत्री ने की सराहना

बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनटाइड एवं टाइड ग्रांट से किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके माध्यम से सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु गुणवत्ता सुधार से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर नगर निगम ने वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक प्राप्त कर देश में छठा स्थान हासिल किया है। राज्य स्तरीय वार्ड रैंकिंग-2026 में रायपुर के वार्ड क्रमांक 46 ने 30 हजार से अधिक आबादी वाली श्रेणी तथा वार्ड क्रमांक 30 ने 10 हजार से 30 हजार आबादी वाली श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और नगर निगम की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के साथ स्वस्थ और बेहतर शहरी जीवन के लिए हरित क्षेत्र भी जरूरी हैं। उन्होंने वार्डों में उद्यान विकसित करने तथा जिन क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या कम है, उनका चिन्हांकन कर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देते हुए प्रत्येक नगरीय निकाय में अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।

भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी पर लोक भवन में सांस्कृतिक संध्या

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत रत्न एवं प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और फिल्मकार डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर आज लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।

राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया तथा उनकी कालजयी रचनाओं और जीवन-यात्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका का संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं

था, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता की गहरी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देती हैं।

सांस्कृतिक संध्या में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कलाकारों ने डॉ. भूपेन हजारिका के जीवन एवं रचनाओं पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। नृत्य के माध्यम से उनकी रचनाओं और जीवन-यात्रा को प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया

गया। महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति, पंडरी, रायपुर के कलाकारों ने डॉ. हजारिका द्वारा गाए प्रसिद्ध गीतों की भावपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी।

राज्यपाल रमेन डेका ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

नि:स्वार्थ सेवा और मानवता की मिसाल है डॉ. राजेश्वरी अम्मा का जीवन : ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में माता डॉ. सी. राजेश्वरी जी के प्रेरणादायी जीवन और मानवता की नि:स्वार्थ सेवा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म **DR. AMMA – 50 Years of Healing, Humanity & Hope"** की स्क्रीनिंग आयोजित हुई। कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेताम एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी शामिल हुए।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि माता डॉ. सी. राजेश्वरी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और करुणा की प्रेरणादायी गाथा है। डॉक्यूमेंट्री

फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, कार्यों और समाज के प्रति योगदान को लाखों लोग जान सकेंगे तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि नि:स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले व्यक्तित्व समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत होते हैं।

डॉ. राजेश्वरी अम्मा जी का जीवन यह संदेश देता है कि सेवा का संकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।

वित्त मंत्री चौधरी ने इस पुनीत अवसर पर सत्य साई परिवार सहित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में राजनांदगांव के पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं सत्य साई परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

जनदर्शन बना जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का मंच

श्रीकंचनपथ समाचार

मुंगेली। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में जिले में आम नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट में आयोजित किए जा रहा जनदर्शन कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड मुंगेली के ग्राम करूपान निवासी महेंद्र कुमार साहू के लिए जनदर्शन का दिन उनके जीवन में नई सुविधा और आत्मनिर्भरता की सौगात लेकर आया। महेंद्र कुमार साहू ने जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के समक्ष अपनी आवश्यकता बताते हुए बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। महेंद्र ने बताया कि आवागमन में परेशानी के कारण उन्हें रोजगार से जुड़े कार्यों तथा घरेलू कामकाज के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी आवश्यकता को समझते हुए कलेक्टर तोपनो ने मामले को गंभीरता से लिया और आवेदन के तत्काल निराकरण के लिए समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महेंद्र कुमार साहू को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद महेंद्र के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। लंबे समय से आवागमन में आ रही परेशानी के बीच यह सुविधा उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। बैटरी चलित ट्राईसाइकिल मिलने से महेंद्र कुमार साहू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने के लिए दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वे अपने रोजगार से जुड़े कार्यों के लिए आसानी से आवागमन कर सकेंगे और घर के आवश्यक कामकाज

भी पहले की तुलना में अधिक सहजता से कर पाएंगे।

महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि पहले किसी काम के लिए बाहर जाने में काफी परेशानी होती थी और समय भी अधिक लगता था। अब बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की मदद से वे अपेक्षाकृत आसानी से अपने आवश्यक कार्य पूरे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा उनके लिए केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चलित ट्राईसाइकिल मिलने पर महेंद्र कुमार साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन मुंगेली के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में अपनी समस्या रखने के बाद जिस तेजी से उनकी मांग पर कार्रवाई हुई, उससे उन्हें काफी खुशी हुई है।

इस दौरान बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर जी.एल.यादव, समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक नदीम काजी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

को-ऑपरेटिव बैंको में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही में लाए तेजी : मंत्री केदार कश्यप

मंत्री कश्यप ने सहकारी सप्ताह 2026 पर आधारित काफी-टेबल बुकलेट का किया विमोचन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मंत्री केदार कश्यप ने बैठक में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। बैठक में मंत्री कश्यप ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा। उन्होंने को-आपरेटिव बैंको में रिक्त पदों की समीक्षा की। उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने सहकारी सप्ताह 29 जून से 06 जूलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव सेक्टर में आयोजित विविध कार्यक्रम पर केन्द्रीत काफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया गया।

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित

मंत्री कश्यप ने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से चालू खरीफ सीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री श्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया। ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

718 गोदामों का निर्माण पूर्ण: मंत्री कश्यप ने 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण व त्वक्थ् योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में आराईडीएफअंतर्गत आबंटित 725 गोदामों में 718 गोदामों के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष 7 गोदाम के जल्द ही निर्माण पूर्ण किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

'अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों को दिलाने निर्देश'

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के आदेश दिए गए।

बैठक के अंत में मंत्री कश्यप ने सभी विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिये। इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ सी.आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता व पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर, अपर पंजीयक यू बीएस राठिया, अपर पंजीयक श्रीमती सावित्री भगत व सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के अधिकारीगण तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950